HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 मार्च, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल
वर्ष 1/ अंक 16/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

राष्ट्र उन्नति में ही व्यक्ति की उन्नति समाहित है....राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

महिला सशक्तिकरण में संस्था की उड़ान

आईआईआरडी को राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक और बड़ी उपलब्धि

2ND BEST INNOVATIVE PRACTICES AWARD FOR WOMEN AT WORKPLACE

दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त करते आईआईआरडी के (दांए से बांए) प्रबन्ध निदेशक डॉ. एल.सी. शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा, रीता वर्मा , महरीन इकबाल ,और आर के सिंह

द रीव टाइम्स ब्यूरो : (हेम राज चौहान)

आईआईआरडी को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि से नवाज़ा गया है । संस्था का चयन कार्यस्थल पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्कृष्ठ माहौल के लिए **यूनाइटिड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ईंडिया** द्वारा चयन किया गया है। इसके तहत जिन मापदंडों पर इसके लिए चयन होता है उसमें आईआईआरडी की सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। गौरतलब है कि आईआईआरडी द्वारा देश भर में किए जा रहे विकासात्मक कार्यों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण दिया गया है। समय–समय पर महिलाओं के लिए संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास नियमित रुप से किए जाते हैं जिससे महिला सशक्तिकरण में संस्था के प्रयासों को पुरस्कृत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यस्थल में संस्था महिला कर्मचारियों के लिए बाक़ायदा सारे नियमों का अनुसरण करते हुए संस्था की ओर से भी विशेष प्रयास किए जाते हैं ताकि उनकी सेवाओं को दिशा प्रदान की जा सके। राजधानी दिल्ली में संस्था की ओर से प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने संस्था की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि आईआईआरडी में महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले समान अनुपात है और कार्यालय में निचले स्तर से उच्च स्तर तक महिलाओं ने अपनी योग्यता को साबित किया है । इसके लिए संस्था ने महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार से सशक्तिकरण के लिए नायाब प्रयास किए हैं । इन्हीं प्रयासों के कारण इस क्षेत्र में भी संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और सम्मानित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है ।

ख़बर मिलते ही हिमाचल प्रदेश आईआईआरडी कार्यालय शनान में सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर छा गई और निदेशक सुषमा शर्मा ने एक प्रैस कांफ्रेस कर इसकी जानकारी दी । उन्होंने द रीम टाइम्स को बताया कि आईआईआरडी को राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान यह बताता है कि हम महिला सशक्तिकरण में बेहतरीन सेवाऐं दे रहे हैं । उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ इस क्षण को साझा कर बधाई दी।

उधर, द रीव टाइम्स से बातचीत में प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने दिल्ली से बताया कि संस्था के महिला सशक्तिकरण एवं कार्यालय में एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली है। उसी प्रकार लैंगिक समानता में भी संस्था के प्रयास सर्वथा सराहनीय रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पूरी आईआईआरडी टीम को बधाई दी।

प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा एवं निदेशक सुषमा शर्मा विशेष रुप से इस समारोह में उपस्थित रहे। उनके साथ आर के सिंह, महरीन इक़बाल और रीता वर्मा भी उपस्थित रहीं । आईआईआरडी के चेयरमैन आर के गुप्ता ने इस पुरस्कार के मिलने के बाद संस्था को बधाई दी है ।

यूनाईटिड नेशंस ग्लोबल कॉंपेक्ट नेटवर्क ईंडिया विश्व में व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए कृत्संकल्प और प्रतिबद्ध है ताकि एक स्थाई और सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण नीतियों को अपनाया जा सके । यह विश्व की 170 से अधिक देशों में 13000 से अधिक व्यवसायिक भागीदारों एवं स्टेकहोल्डरस के साथ कार्य कर रही एक विश्वव्यापी पहल है।

आतंक की तेरहवीं, 13 दिन बाद घर में घुस कर पाकिस्तान को धूल चटाई

भारतीय वायुसेना ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों के चिथड़े उड़ाए

द रीव टाइम्स ब्यूरो: (हेम राज चौहान)

जैसी करनी वैसी भरनी.....पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन कर पुलवामा जैसे जघन्य अपराध पर चुप्पी साध ली थी लेकिन भारतीय जवानों ने 13 दिन के बाद सूद सहित बदला ले लिया। मध्य रात्रि के बाद सुबह का सूरज जब उगा तो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया तो पाकिस्तान में जैश–ए–मुहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बारुदी हमले से दहशत का माहौल बन गया। 13 दिन बाद भारत ने घर में घुस कर आतंकीस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों को तबाह कर दिया। मसूद का आतंकी ठिकाना भी सेना की जद में था और इसको भी निस्तेनाबूत कर दिया गया। गौरतलब है कि पुलवामा के बाद पूरा देश बदले की आग में झुलस गया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार रैलियों और जनसभाओं में कह रहे थे कि समय का इंतज़ार करें। यह इंतज़ार 13वें दिन ख़त्म हुआ और एक बार फिर से भीतर घुस कर 21 मिनट तक आतंकीस्तान के ठिकानों के बख़्खियां उधेड़ दी गई। इस कार्यवाही में ख़बर लिखे जाने तक भारतीय सेना को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन आतंकी ठिकानों पर सैंकड़ों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उधर पाकिस्तान में हड़बड़ी है और भारत की घर में घुसकर की गई कार्यवाही पर स्तब्ध भी।

36 घंटों में ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकली

पायलट अभिनंदन को पकड़ने के बाद आनन–फानन में ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी उस समय निकल गई जब सुबह अभिनन्दन को बंदी बनाने के बाद समझौता करने की बात करने के बाद इमरान ने असेंबली में शाम को कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान 1 मार्च को रिहा कर देगा । 1 मार्च को पायलट को रिहा कर भी दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को पायलट को छोड़ना ही था.....इसका अर्थ यह बिल्कुल न निकाला जाए कि भारत आतंकवाद पर की जा रही कार्यवाही पर रत्ति भर भी ढील देगा । उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर पारदर्शी और सख़्त कार्यवाही नहीं करता, भारत की कार्यवाही और अधिक सख़्त होती जाएगी । उन्होंने कहा कि यह तो केवल रिहर्सल थी ....असली कार्यवाही तो अब होगी ।

बहुत सी अपेक्षाओं के साथ नगर निगम का संतुलित बजट

297.52 करोड़ से शिमला को बनाऐंगे स्मार्ट

स्मार्ट सिटी और जल प्रबन्धन बोर्ड को नहीं किया गया शामिल

महापौर कुसुम सदरेट ने पेश किया टैक्स फ्री सरप्लस बजट

बजट से होगा शिमला का कायाकल्प : महापौर

द रीव टाइम्स से बातचीत में महापौर नगर निगम शिमला कुसुम सदरेट ने बताया कि निगम के बजट 2019–2020 के लिए हर तबके और आदमी को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया । इस बजट में शिमला को आदर्श एवं स्मार्ट बनाने में मदद मिलेगी । उन्होंने बातचीत में बताया कि शिमला के चंहुमुखी विकास के लिए प्रप्येक वार्ड के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है । उन्होंने कहा कि शहर में युवाओं, युवा मंडलों के लिए खेल मैदान आदि की व्यवस्था की जाएगी । साथ ही सब–वे और टैस्ट लैब को भी जनता के लिए शुरु किया जा रहा है । महिला सशक्तिकरण पर उनकी विशेष पहल है और इसके लिए उन्होंने बताया कि चौड़ा मैदान में इस प्रकार का महिला सशक्तिकरण केन्द्र स्थापित किया गया है । आवारा गायों के लिए ज़मीन का चयन कर शैड बनाये जाऐंगे ।

लोगों को ठगा गया इस बजट में : शैली शर्मा, पार्षद ,सीपीएम

द रीव टाइम्स को बताया कि 2017 तक के सभी प्रोजेक्ट को ही इस बजट में दोहराया गया है और कुछ भी नया नहीं है । केन्द्र और राज्य सरकार की कोई भी ग्रांट निगम को नहीं मिली जबकि दोनों जगह इन्हीं की सरकार बैठी है । नया टॉउन हॉल बनाने का प्रोपेगेंडा करने से बढ़िया होता कि जो पुराना है उस संभालें । पिछले बजट में वायदा किया गया था कि सस्ती बिजली और बिलों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाऐगा जबकि एक कंपनी से समझौता करे लोगों को धोखे में रखा और अब बिलों की उपलब्धता और सस्ती बिजली जैसे जुमले खोखले ही साबित हुए हैं। शैली शर्मा ने बताया कि उन्होंने ट्रैफिक, आवारा कुत्तों एवं गाय, स्वच्छता को लेकर तीन सुझाव दिए थे जिन पर निगम के इस बजट में गंभीरता से कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया है ।

पुराना माल...नया पैकेट दिवाकर देव शर्मा, पार्षद, कांग्रेस

निगम ने लोगों से बजट के लिए सलाह मांगी थी जिसे एक प्रतिशत भी बजट में नहीं दर्शाया गया । पिछले कुछ वर्षों की तर्ज़ पर खोखला बजट पेश किया गया है । बजट आंकड़ों का खेल है जो कि निगम ने इधर से उधर कर लोगों को गुमराह किया है । युवाओं, महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नया नहीं है।

शिमलावासियों के उद्गार :

बजट को संतुलित बनाया गया है लेकिन इसमें मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी हुई है । शहर को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की बात हर साल बजट में होती है पर एक मज़बूत योजना के साथ लागु नहीं हो पाता है । ट्रैफिक एक भयंकर समस्या है, उस पर कोई ठोस योजना नहीं है । सफाई एवं कुत्तों की समस्या से शिमला को निजात मिले इस पर भी निगम के पास योजना का अभाव है । पार्किंग और तहबाजारियों के लिए निगम बजट में स्पष्ट नहीं है ।

उमा शंकर, सामाजिक कार्यकर्ता

शिमला को स्टील के डस्टबिन से गुलजार करेगा आईआईआरडी : प्रबंध निदेशक

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने बजट को सराहनीय बताया और कहा कि इसमें बहुत कुछ समस्याओं का ज़िक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि शिमला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में आईआईआरडी भी अपना हर संभव सहयोग देगा। जिसके तहत एक प्रस्ताव शिमला शहर में अत्याधुनिक स्टील कुड़ेदान लगाने का संस्था ने नगर निगम को दिया है तथा शीघ्र ही शहर को इसकी उपलब्धता करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

शिमला के लिए एक संतुलित बजट : राकेश शर्मा

द रीव टाइम्स ब्यूरो से बातचीत में नगर निगम उप–महापौर राकेश शर्मा ने इस बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है । बजट को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सरवीण चौधरी और सुरेश भारद्वाज के परामर्श के अनुसार ही जनोपयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है । निगम के सीमित साधनों के बावजूद इसकी व्यापक पैमाने पर रुपरेखा तैयार की गई है ।

ट्रैफिक समस्या का निदान कैसे होगा, पार्किंग के लिए भी निगम ने बजट में कुछ ख़ास प्रावधान नहीं किया है ।

निधि शर्मा, सदस्य उद्घोष ट्रस्ट

भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद आर्मी कैंट योल में हाई अलर्ट

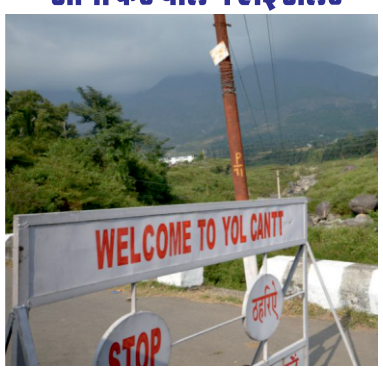

द रीव टाइम्स

पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय वायु सेना के हमले के बाद हिमाचल के कांगड़ा में योल स्थित सेना की 9वीं कोर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरा सेना क्षेत्र सील कर दिया गया है। यहां से आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आर्मी कैंट योल में केंद्रीय स्कूल और आर्मी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी है।

हि.प्र.ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के तहत समझौता ज्ञापन समारोह

ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के तहत 17356 करोड़ रुपये के निवेश के 159 समझौता ज्ञापनों पर किए गए हस्ताक्षर

प्रदेश में 40 हजार से अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सरकार प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को और आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्योग, पर्यटन, वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक, अरोमा, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रिकल व्हीकल, फिल्म तथा आयुष के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टर मीट के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के लिए धारा–118 पर ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक समझौता ज्ञापन के अतिरिक्त पर्यटन, वैलनेस, परिवहन, आवास तथा भाषा, कला एवं संस्कृति इत्यादि के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 159 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे प्रदेश में लगभग 17,356 करोड़ रुपये का कुल निवेश व 40,911 से भी ज्यादा लोगों के लिए रोज़गार के अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में 1115 करोड़ रुपये के तीन, उद्योग क्षेत्र में 5243 करोड़ के 88, पर्यटन एवं नागरिक उड्यन में 2810 करोड़ के 36, शहरी विकास में 4331 करोड़ के 17, भाषा कला एवं संस्कृतिक क्षेत्र में 25 करोड़ का एक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 685 करोड़ रुपये के दो, आयुर्वेद क्षेत्र में 357 करोड़ रुपये के छः, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये का एक तथा परिवहन क्षेत्र में 2780 करोड़ रुपये के पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा तथा शिमला में तीन हवाई अड्डों के अतिरिक्त 63 क्रियाशील हैलीपेड हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्गों का बेहतर नेटवर्क उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष जून माह में धर्मशाला में 'ग्लोबल इन्वेस्टर मीट' आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और आयुष, विनिर्माण, फार्मासियूटिकल, अधोसंरचना और लॉजीसिक्टस, ऊर्जा एवं नवीकर्णिय

ऊर्जा, एग्रो और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्य सचिव बी.के अग्रवाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिभा और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई.आई.टी मण्डी और आई.आई.आई.टी ऊना आदि जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रमुख शैक्षणिक

अब लाहौल से पाकिस्तान निर्यात नहीं किया जाएगा आलू बीज

हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र लाहौल घाटी में उत्पादित बीज आलू को अब कभी भी पाकिस्तान को निर्यात नहीं किया जाएगा। पुलवामा में भारतीय जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद सोलन ने टमाटर, सिरमौर ने अदरक, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा ने कत्था की फसल को पाकिस्तान भेजने से पहले ही मना कर दिया है। इसी बीच लाहौल पोटेटो सोसायटी (एलपीएस) ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का एलान कर दिया है।

चंबा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

भारतीय वायुसेना की ओर से आंतकी ठिकानों पर हमले के बाद चंबा में जम्मू–कश्मीर से सटी सीमाओं और थानों में अलर्ट जारी किया गया। डलहौजी कैंट एरिया, एयरफोर्स स्टेशन गांधी चौक, डेनकुंड एयरफोर्स स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू से लगती सीमाओं, राज्यों के साथ लगते बेरियरों पर चौकसी बरती जा रही है। तीसा, खैरी, किहार के सीमांत क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट जारी किया है। वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पाकिस्तान को कत्था और आलू बीज निर्यात नहीं करेंगे हिमाचल के कारोबारी

शिमला हिमाचल से अब पाकिस्तान को कत्था का निर्यात नहीं होगा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कारोबारियों में आक्रोश है। प्रदेश कत्था उद्योग के कारोबारियों ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कत्था का कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा।

कत्था उद्योगपतियों के मुताबिक हिमाचल से हर साल टनों की मात्रा में कत्था का निर्यात पाकिस्तान के लिए किया जाता है। कत्था के निर्यात से करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। प्रदेश से कत्था को दिल्ली और कोलकाता के लिए भेजा जाता है।

इसके बाद भारत में कत्था के डीलर पाकिस्तान के कराची के लिए कत्था की सप्लाई करते हैं। जानकारी के मुताबिक हर साल करीब 20 से 25 बार कत्था का निर्यात पाकिस्तान के लिए होता है।

प्रदेश के कत्था कारोबारियों के मुताबिक फैक्ट्रियों में खैर की लकड़ी से कत्था को बनाया जाता है। कत्था के दाम अधिक हैं जबकि कत्था से निकाले गए बनजबी (काछ) की कत्था के मुताबिक कम दाम हैं। पाकिस्तान को डिमांड के हिसाब से कत्था निर्यात किया जाता है।

पान मसाले में कत्था का उपयोग

कत्था (काछ) का उपयोग पान के मसाले में किया जाता है। पाकिस्तान में लाखों किसान और गरीब लोग कत्था का उपयोग खाने के पान के इस्तेमाल करते हैं।ही पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश ने इंडिया टूडे पर्यटन अवार्ड–2019 में जीते तीन अवार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह राज्य पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य स्थल है, जब राज्य ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में इंडिया टूडे पर्यटन अवार्ड समारोह में सबसे अधिक अवार्ड प्राप्त किए। राज्य ने सर्वश्रेष्ठ 'साहसिक गंतव्य', 'सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी गंतव्य' एवं 'सर्वश्रेष्ठ सुरम्य सड़क' में तीन द्वितीय अवार्ड इंडिया टूडे पर्यटन सर्वेक्षण व पुरस्कार–2019 के दौरान नई दिल्ली में आज आयोजित समारोह में प्राप्त किए। केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के.जे. एलफोन्स ने राज्य को यह अवार्ड प्रदान किए, जिन्हें उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य श्रेणी में हैंग ग्लाईडिंग बीड़ बिलिंग को सर्वश्रेष्ठ द्वितीय अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी गंतव्य की श्रेणी में किन्नौर ज़िला के सांगला को द्वितीय पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ सुरम्य सड़क श्रेणी में शिमला–जिस्पा वाया काजा स्ट्रेच को द्वितीय अवार्ड के लिए चुना गया।

विभिन्न राज्यों को नौ श्रेणियों में यह अवार्ड दिए गए, जिसमें से हिमाचल प्रदेश ने तीन श्रेणियों में ये अवार्ड जीते।

हिमाचल के जवान पर गिरा हिमखंड, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गांव में नहीं जले चुल्हे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शाहतलाई के गांव घुमारपुर के राकेश कुमार गश्त के दौरान किन्नौर में हिमखंड की चपेट में आने से शहीद हो गए । सूचना मिलते ही क्षेत्र में मातम छा गया है । राकेश कुमार सेना में कार्यरत थे और वर्तनाम में किन्नौर जिला में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यहां हिमखंड की चपेट में आने से उनकी भी मौत हो गई।

परिजनों को हादसे की सूचना शाम करीब चार बजे मिला जब किन्नौर से राकेश के पिता को फोन आया । सूचना मिलते ही पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा । राकेश अपने माता–पिता की इकलौती संतान थी । राकेश अपने पीछे माता–पिता, पत्नी और बच्चों को छोड़ गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले। एसपी बिलासपुर अशोक कुमार ने बताया कि मृतक सैनिक शाहतलाई क्षेत्र से संबंध रखता है। सैनिक का पोस्टमार्टम कर दिया गया ।

वहीं, देर रात जैसे ही पिता चिरंजी लाल को फोन आया तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। हादसे की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही लोगों का राकेश के घर पहुंचना शुरू हो गए । वहीं, सूचना मिलने के बाद माता–पिता के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ल रहे।

जबकि पत्नी बेसुध पड़ी हैं। वहीं, हादसे की सूचना मिलने के बाद घुमारपुर में लोगों के तांता लग गया । पंचायत प्रधान घराण पुनम कुमारी और वार्ड सदस्य रणजीत सिंह ने बताया की सूचना करीब 2 बजे मिली ।

राकेश कुमार अपने पीछे पिता चिरंजी लाल, माता कौशल्य देवी, पत्नी ममता देवी, दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बड़े बेटे मनीष और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विवेक को छोड़ गए। उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया की किन्नौर में हुए हादसे की सूचना परिजनों को दी गई है।

गौर हो कि किन्नौर जिले में भारत–चीन सीमा से सटे दुर्गम क्षेत्र नमज्ञा में गश्त पर निकले सेना के छह जवान भारी हिमस्खलन में दब गए हैं। इनमें एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 5 सैनिकों का अभी तक कोई अता–पता नहीं है।

राज्यपाल ने तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्रियां वितरित की

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। उद्योग और तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह इस अवसर पर बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा छात्र जीवन जीता है और अपने जीवन में हमेशा नया सीखने की जिज्ञासा रखता है, वह सही मायनों राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देता है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों से कहा कि आपको आज डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं, लेकिन यह अन्त नहीं है बल्कि ज्ञान, सृजनात्मकता तथा जीवन भर सीखने की इच्छा रखने की एक नई शुरूआत है।

दीक्षांत समारोह की प्राचीन परम्परा को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि उपनिषदों में यह पहले से अकिंत है कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का एक भाग है, जहां पर शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अध्यापक छात्रों को समाज की उन्नति के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करते हैं। दीक्षांत समारोह के समय जो दिशा–निर्देश दिए जाते थे, उनमें यह प्रमुख था कि छात्रों को ईमानदारी का बर्ताव करने के साथ–साथ अपने ज्ञान को जीवन भर लगातार बढ़ाना चाहिए तथा इसे समाज में भी बांटना चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। उन्हांने कहा कि ऐसे दिशा–निर्देशों और समृद्ध परम्पराओं का पालन करने के लिए यह उचित समय है।

जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध होंगी बैरा परीक्षण सुविधाएं: मुख्य सचिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य सचिव बी.के अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को श्रेष्ठ शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

मुख्य सचिव अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष रूप से सक्षम बच्चों के ढली (शिमला)और सुन्दरनगर संस्थानों द्वारा मूक, बधिर और दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि ढली स्थित संस्थान के छात्रों का चिकित्सा परीक्षण इन्दिरा गांधी मेडिकल शिमला में किया गया जिसमें विभिन्न बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया। सुन्दरनगर संस्थान के छात्रों का भी चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है तथा उन्हें भी आवश्यक यंत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रवण दोष से पीड़ित बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण (बैरा टेस्ट) को बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य के जिला स्तरीय अस्पतालों में भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी श्रेणियों के 91,958 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें से 11473 श्रवण दोष से पीड़ित हैं। विभाग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष रूप से सक्षमों के अपंगता को जॉचने व सूचीबद्ध करने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा, जिससे ऐसे व्यक्तियों की पहचान व उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसे युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त, सूजोप योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोज़गार व स्वरोज़गार प्राप्त करने में मदद मिल सकें।

अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के निदेशक हंसराज चौहान ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए इन संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।

एक नजर में जयराम सरकार का दूसरा बजट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- जीएसटी में पंजीकरण हेतु वार्षिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा । टर्नओवर की कंपोजिशन लिमिट बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए की जाएगी ।
- एनपीएस के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत अंशदान को 14 प्रतिशत किया जाएगा । इससे 80,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा ।
- पहली जुलाई, 2018 से प्रदेश के कर्मचारियों को चार प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता तथा पेंशनधारकों को मंहगाई राहत ।
- अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी । वेतन और ग्रेड–पे में 125 प्रतिशत की दर से राशि जोड़ी जाएगी ।
- नूरपुर में युद्ध स्मारक का निर्माण होगा। राज्य आपदा राहत बल का गठन किया जाएगा ।
- आपातकाल के दौरान एमआईएसए के अंतर्गत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि ।
- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण ।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 850 रुपए प्रतिमाह पांच लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ ।
- 'गृहिणी सुविधा योजना' और 'उज्ज्वला' के लाभार्थियों को अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 750 रुपए प्रतिमाह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं–सहायिकाओं, आशा वर्कर्ज, वाटर गार्ड, वाटर कैरियर्ज, मिड–डे मील वर्कर्ज एवं सहायकों, पंप आपरेटर्र, पैरा फिटर, चौकिदारों का मानदेय बढ़ाया ।
- ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अंतर्गत अब 20,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे । मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मरम्मत हेतु सहायता राशि 35 हजार ।
- युवा नव जीवन बोर्ड बनाया जाएगा । पांच नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र खुलेंगे ।
- गरीब मरीजों के लिए 'सहारा' योजना शुरू होगी । पार्किंसंस, कैंसर, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, रिनल फेलियर मरीजों को 2000 रुपए महीना
- एड्स पीड़ितों को 1500 रुपए प्रतिमाह। 'जननी सुरक्षा योजना' के तहत प्रोत्साहन राशि 1100 रुपए ।
- 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को नर्सिंग इंस्टीच्यूशंस में प्रवेश हेतु आरक्षण। परित्यक्ता महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता 6000 रुपए
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के लिए 'आफ्टर केयर होम' स्थापित किए जाएंगे ।
- 50 दिन से ज्यादा काम करने वाले मनरेगा लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पाने वाली विधवाओं के लिए हिमकेयर योजना ।
- 7100 करोड़ की वार्षिक योजना कृषि, गांवों में आधारभूत ढांचा सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और सामाजिक क्षेत्र पर केंद्रित ।
- मुख्यमंत्री स्वजल योजना में गरीब परिवारों को नलका लगाने के लिए 50 मीटर तक पाइप के लिए 50 प्रतिशत उपदान ।
- मुख्यमंत्री रोशनी योजना शुरू होगी, जिसके तहत गरीब परिवारों को नए बिजली कनेक्शन हेतु कोई सर्विस चार्जिज नहीं देने पड़ेंगे ।
- 1,688 करोड़ की एचपी सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन एंड वैल्यू एडीशन योजना बाह्य सहायता के सहयोग से चलेगी ।
- 11.21 करोड़ से साहिवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा ।
- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय बढ़ाने के लिए 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी ।
- 11 करोड़ की लागत से मुर्राह नस्ल की भैंसों का फार्म बनेगा । एक गोकुल ग्राम भी स्थापित होगा ।
- दत्तनगर जिला शिमला एवं चक्कर जिला मंडी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र ।
- परंपरागत कौशल और शिल्प ग्राम कारीगर, शिल्पी एवं अन्य के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना' प्रारंभ होगी ।
- ऊना और चंबा जिलों में 'एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना' आरंभ की जाएगी ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 लकड़ी के खंबे लोहे के खंबों से बदले जाएंगे, ताकि नियमित बिजली मिले ।
- किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम कर 50 पैसे प्रति यूनिट ।
- 'पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड' का गठन होगा, जो क्षेत्र के समुचित एवं सुनियोजित विकास पर नीति एवं कार्यक्रम तय करेगा
- पर्यटन विकास और प्रोत्साहन क्षेत्र के लिए नई पर्यटन नीति तैयार होगी । होम स्टे स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाकर चार की जाएगी ।
- हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए हेलिटैक्सी सेवाएं शुरू की जाएंगी । नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी आएगी ।
- धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंडी जिला में 'शिव धाम' स्थापित किया जाएगा ।
- परिवहन निगम में इंटेग्रेडिट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीटीएमएस) प्रणाली की स्थापना की जाएगी ।
- 500 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं चालू होने की संभावना। इसमें सौ मेगावाट की उहल–तृतीय चरण तथा 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू परियोजनाएं शमिल हैं। चांजू–तीन और दियोथल चांजू का कार्य शुरू किया जाएगा ।
- कौशल विकास भत्ता योजना के तहत लगभग एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । कौशल विकास निगम द्वारा 40000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।
- ग्रामीण दस्तकारों का कौशल बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना आरंभ की जाएगी ।
- 50 आईटीआई को अपग्रेड कर आधुनिक बनाया जाएगा । भंजराडू, तीसा, अंबोया, सतौन और लड़भड़ोल में पांच नई आईटीआई । करसोग और दलाश में पोलीटेक्नीक कालेज ।
- विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक पंजीकृत युवक मंडलों को 25,000 रुपए तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण प्रति युवक मंडल प्रदान कर पाएंगे ।
- एसएसबी कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राशि छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार । वर्ष 2019–20 में लगभग 20000 पद भरेंगे ।
- 15 नए अटल आदर्श विद्या केंद्र प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। खेल से स्वास्थ्य योजना आरंभ की जाएगी ।
- नई 'अटल निर्मल जल योजना' के तहत स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर लगेंगे । 'एक बूटा, बेटी के नाम' योजना चलेगी ।
- परफार्मिंग आर्ट्स में प्रोत्साहन हेतु 'कलाकार प्रोत्साहन योजना' शुरू की जाएगी ।
- 500 स्वास्थ्य उपकेंद्रों तथा 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदलेंगे ।
- लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मंडी व वाईएस परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में हृदय रोगों का उपचार होगा । आईजीएमसी में डिजिटल सबस्ट्रेशन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित होगी ।

जयराम सरकार ने बदले 23 बीडीओ

चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेशों के चलते जारी की अधिसूचना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जयराम सरकार ने गुरुवार को प्रदेश के 23 विकास खंड अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं । केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेशों की पालना करते हुए सरकार ने बीडीओ के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत डीआरडीए कांगड़ा में तैनात रेखा कुमारी को धर्मपुर भेजा गया है। ऊना में सेवाएं दे रहे सुदर्शन सिंह को डीआरडीए सिरमौर में तैनाती दी गई है। चंबा जिला के सलूनी में कार्यरत इंदु बाला को कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरियां बदला गया है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में तैनात किशन चंद को कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में तैनात किया गया है। जिला मुख्यालय चंबा से सटे मैहला ब्लॉक में तैनात सुशीला को इंदौरा ब्लाक में भेजा गया है । जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित ब्लॉक में लंबे समय से सेवारत अस्मिता को ब्लॉक खंड कांगड़ा में तैनात किया गया है। यह पद रिक्त चल रहा था। हमीरपुर जिला के बमसन ब्लॉक में तैनात यशपाल सिंह को ऊना विकास खंड में भेजा गया है। कांगड़ा जिला के ब्लॉक नगरोटा बगवां में कार्यरत रमेश कुमार को हमीरपुर के बमसन में तैनाती दी गई है। कांगड़ा जिला के रैत ब्लॉक से मनीष कुमार को चंबा जिला के मैहला विकास खंड में भेजा गया है । कांगड़ा जिला के भेडू महादेव से सिकंदर को मंडी जिला के बाली चौकी में तैनाती आदेश दिए गए हैं। कांगड़ा जिला के विकास खंड धर्मशाला में सेवाएं दे रहे अभिनीत कात्यान को हमीरपुर विकास खंड में भेजा गया है। मंडी जिला के बल्ह एट नेरचौक में सेवाएं दे रहे विकास खंड अधिकारी बशिर को चंबा जिला के भटियात में ट्रांसफर किया गया है। चेतराम को बाली चौकी से कांगड़ा के लंबा गांव भेजा है। अनूप कुमार को सिरमौर जिला के नाहन से शिमला के विकास खंड ठियोग में भेजा गया है। सोलन जिला के धर्मपुर में तैनात रवि कुमार बैंस को शिमला जिला के विकास खंड ठियोग में तैनाती दी गई है। हेमचंद को सोलन के नालागढ़ से ऊना जिला के गगरेट में ट्रासंफर किया है। प्रताप चौहान को शिमला के ठियोग से चंबा के सलूनी भेजा गया है। शिमला जिला के नारकंडा में तैनात मरिकाना देवी को नारकंडा से सोलन के धर्मपुर ब्लॉक में तैनाती दी गई है। शिमला के चौपाल में तैनात रोशन लाल को बिलासपुर जिला के ब्लॉक खंड झंडुता में रिक्त पद पर भेजा गया है। राजेंद्र सिंह को शिमला जिला के कुपवी से मंडी के करसोग विकास खंड में भेजा गया है। विजय कुमार नेगी को शिमला के छोवारा से मंडी जिला के बल्ह एट नेरचौक भेजा है। शिमला जिला के जुब्बल विकास खंड में तैनात सतपाल सिंह को इसी जिला के कुपवी ब्लॉक में तैनाती दी गई है। विकास खंड ऊना में सेवाएं दे रहे राजकुमार को सोलन के नालागढ़ ट्रांसफर किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी 23 विकास खंड अधिकारियों के तबादला आदेशों की अधिसूचना जारी कर इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। सरकार ने अपने आदेशों में कहा है कि चुनाव आयोग से जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पिछले चार सालों से तीन साल एक ही जगह सेवाएं दे रहे विकास खंड अधिकारियों को बदला गया है।

हजारों लोगों को पानी के घरेलू कनेक्शन देने की तैयारी, एमसी शिमला ने लिया फैसला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नगर निगम की मासिक बैठक में मर्ज एरिया में रहने वाले हजारों उपभोक्ताओं को पानी के बिलों में रियायत को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मर्ज एरिया में जिन लोगों के पुराने मकान हैं और जिनसे व्यवसायिक दरों पर पानी के बिल लिए जा रहे हैं उन्हें राहत देने की तैयारी की गई है।

नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो दो महीने के भीतर मर्ज एरिया में आने वाले पुराने भवन मालिकों की सूची बनाएगी और उनके पानी के व्यवसायिक कनेक्शन को घरेलू करने के लिए नगर निगम बायलॉज में बदलाव करने की मंजूरी मांगेगी ।

सदन की स्वीकृति के बाद हजारों उपभोक्ताओं का घरेलू पानी का कनेक्शन लेने का रास्ता साफ हो जाएगा । सदन में पानी के आ रहे ज्यादा बिलों को लेकर खूब हंगामा किया गया ।

कई पार्षदों ने सदन में कहा कि उपभोक्ताओं को 40 –40 हजार तक पानी के बिल आ रहे हैं और कई जगह पर पानी के बिल बंटे ही नहीं हैं। कई जगह पर पानी के मीटर खराब है और उन्हें बदलने के लिए अब उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि वह अपने पैसों से इन्हें बदले।

21 सुपरवाइजरों की कटी तनख्वाह

सैहब सोसाइटी में रखे गए 21 सुपरवाइजरों के मासिक वेतन पर नगर निगम ने कैंची चलाई है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये सुपरवाइजर डोर टू डोर गारेबज फीस लेने में लापरवाही बरत रहे हैं।

हर महीने सैहब पर नगर निगम का खर्च करीब 70 लाख बैठ रहा है और इनके पास कलेक्शन मात्र 30 से 32 लाख आ रही है। बार बार टारगेट देने के बावजूद कई सुपरवाइजर चेतावनी को हल्के से लेते रहे। एक सुपरवाइजर ऐसा भी है जिसकी कलेक्शन जीरो फीसदी है तो ऐसे सुपरवाइजर को किस बात की तनख्वाह। निगम आयुक्त ने कहा कि गारबेज कलेक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा वेतन दिया गया है।

नगर निगम शिमला बजट 2019–2020

मेयर ने 129.37 लाख रुपये का सरप्लस बजट पेश किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नगर निगम ने साल 2019–20 के बजट में पुराने वादों को एक बार फिर दोहरा दिया । कई वादे तो ऐसे हैं जो माकपा शासित नगर निगम के समय में शहर के लोगों से किए जा रहे हैं।

1. पार्किंगों में ओवर चार्जिंग रोकने को मोबाइल ऐप
2. आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू होगी ग्रीन फीस वसूली
3. वेंडिंग जोन में बसाए जाएंगे तहबाजारी
4. आजीविका भवन का निर्माणकार्य होगा पूरा
5. नगर निगम की सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन
6. कंस्ट्रक्शन वेस्ट से तैयार होंगी टाइलें
7. वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से होगा विद्युत उत्पादन
8. आधुनिक मशीनों से होगी शहर की सफाई
9. 24 घंटे सातों दिन पानी, मीटर रीडिंग पर पानी बिल
10. टूटु में बनेगा नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
11. शहर के पुराने एसटीपी होंगे अपग्रेड
12. हिमलैंड, खलीनी, टूटीकंडी में फुट ओवरहेड ब्रिज बनेंगे
13. कृष्णानगर में आवासीय इकाईयों का निर्माण होगा पूरा
14. आशियाना 2 का द्वितीय चरण होगा पूरा
15. वार्डों में बनेंगे नए पार्क और पार्किंग

नगर निगम ने साल 2018–19 के बजट की तर्ज पर साल 2019–20 के बजट में भी महिला सशक्तीकरण के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। खास बात यह है कि पिछले साल की बजट घोषणा पूरी करने के लिए मेयर ने मौजूदा बजट पेश करने से एक दिन पहले 20 फरवरी को चौड़ा मैदान में भगनि निवेदिता महिला सशक्तीकरण केंद्र का शुभारंभ किया।

यह केंद्र कैसे काम करेगा, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। शौचालयों, पार्किंग और वाटर एटीएम की होगी क्यूआर कोडिंग

नगर निगम ने बजट में शहर के शौचालयों, पार्किंगों और वाटर एटीएम की क्यूआर कोडिंग करने का ऐलान किया है। तर्क दिया गया है कि ऐसा करने से शहर के लोगों और सैलानियों को पब्लिक सेवाओं की उपयुक्त जानकारी मिल सकेगी।

बीमा की शिमला से हुई धमाकेदार शुरुआत

मिशन रीव ने किया गांव–गांव में अभियान का आगाज़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी के एलआईसी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट ऐजेंसी में चयन होने के बाद मिशन रीव के तहत ज़िला शिमला में लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए इस माह सराहनीय प्रयास किए हैं । गांव–गांव तक मिशन रीव के तहत बीमा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

रीव आर्गेनिक से बढ़ी फूलों की पैदावार

सोलन में किसान ने एक माह में कमाए 40 हजार

टीम रीव, सोलन

मिशन रीव के तहत सोलन में अनेक पंचायतों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ रही है। सोलन में मिशन रीव के प्रतिनिधि ने बताया कि मिशन रीव की ओर से तैयार करवाई जा रही जैविक खाद सोलन के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका ताजा उदाहरण सोलन जिला के तहत आने वाले झाझा पंचायत के किसान है। सोलन के चायल के तहत आने वाली झाझा पंचायत के किसान वीरेंद्र ने बताया वह काफी समय से फूलों की खेती करते हैं। फूलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले वह रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे। ये खाद काफी मंहगी मिलती है और पैदावार भी खास नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लगातार कम हो रही थी। इसके बाद मिशन रीव की ओर से उपलब्ध कराई जा रही जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में किया। इसके दो लाभ हुए। पहला मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई और दूसरा पैदावार भी मनमाफिक हो गई। वीरेंद्र ने बताया कि आज वह फूलों की खेती से हर माह 40 हजार की कमाई कर रहे हैं। वीरेंद्र की तरह ही अन्य किसान भी मिशन रीव के तहत जैविक खाद के माध्यम से अपनी आर्थिकी बदल रहे हैं। सोलन से किसानों द्वारा तैयार खाद को प्रदेश के अन्य जिलों जैसे किन्नौर और चंबा भेजा जा रहा है। खाद बनवाने से लेकर उसे बाजार उपलब्ध कराना और किसानों को उसकी आय प्रदान करने तक का पूरा काम मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से किया जा रहा है। किसानों का कहना है जैविक खाद का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

नाहन में ईएसआई अस्पताल की रखी आधारशिला

टीम रीव, सिरमौर

नाहन : औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 30 बिस्तर वाले ईएसआइ अस्पताल का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व सांसद लोकसभा प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस अस्पताल को बाद में स्तरोन्नत करके एक सौ बिस्तर का बनाया जाएगा।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ॰ राजीव बिंदल ने कहा कि अस्पताल के निर्माण के लिए लगभग पांच हेक्टेयर भूमि ईएसआइ के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। अस्पताल के बनने से जहां सिरमौर जिला में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों के कार्य करने वाले कुशल एवं अकुशल 35 हजार कामगारों को उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पर स्थानीय लोगों को भी घर–द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल में आपातकालीन, ओपीडी, वार्ड प्रयोगशाला, ऑपरेशन थियेटर, मातृत्व इत्यादि सेवाएं उपलब्ध होगी।इस मौके पर लोकसभा सासंद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि देश में ईएसआइ के 150 अस्पताल और 1500 औषधालय हैं। इनमें औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले 13 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में ईएसआइ के दो अस्पताल परवाणु एवं बद्दी के अतिरिक्त 17 औषधालय कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 12 लाख को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

स्वाइन फ्लू पीड़ितों के घर पहुंचा स्वास्थ्य विभाग

सराहां/ राजगढ़ (सिरमौर)

सिरमौर जिले में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिले के नारग और राजगढ़ के सेर जगास में दो मामले सामने आए हैं। दोनों के टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को दवाइयां वितरित की हैं। वहीं, जरूरी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। पच्छाद क्षेत्र की नारग पंचायत के नारग गांव में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है। सोलन अस्पताल में इलाज को गई महिला के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी पुष्टि हुई है। सराहां सिविल अस्पताल में यह सूचना पहुंच गई है। इसके बाद सराहां से बीएमओ डॉ. संदीप शर्मा की अगुवाई में एक टीम ने नारग का दौरा किया। वे स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज के घर गए और उसके संपर्क में आए लोगों से बात की। बीएमओ पच्छाद डॉ॰ संदीप शर्मा ने बताया कि टीम ने नारग जाकर लोगों को स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूक किया। वहीं, संपर्क में आए कुछ लोगों को दवाइयां भी वितरित की गई हैं। टीम में स्वास्थ्य शिक्षिका अमृता ठाकुर व नरेश परमार समेत कई लोग शामिल रहे।

उधर, सेर जगास में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक किया। सीएमओ डॉ. केके पराशर ने बताया कि विभाग की स्वाइन फ्लू पर पूरी नजर है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पांवटा क्षेत्र में महिला की मृत्यु हुई है। लेकिन, इसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी एहतियात के तौर पर महिला के संपर्क में आने वाले लोगों को दवाइयां वितरित की गई।

रोनहाट में पार्किंग चिन्हित, जाम से मिलेगी निजात

टीम रीव (सिरमौर)

रोनहाट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से उपायुक्त सिरमौर ने पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। एंबुलेंस सेवा व बसों के आवागमन संबंधी परेशानी और जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

अधिसूचना के मुताबिक उपतहसील रोनहाट से लेकर रास्त सड़क तक वाहनों की पार्किंग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। अब रोनहाट बस स्टैंड में बसों के अलावा किसी भी अन्य वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों की पार्किंग के लिए रास्त सड़क पर एक तरफ व तहसील से मंदिर की तरफ भी एक ओर वाहनों को पार्क करने की अनुमति प्रदान की गई है। बाजार में सामान लोड व अनलोड करने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक व दोपहर 3 बजे के बाद ही बाजार में वाहनों से सामान को उतारने व चढ़ाने की अनुमति दी गई है। लिहाजा अब यातायात नियमों को ठेंगा दिखाने वाले वाहन चालकों व वाहन मालिकों पर कानूनन शिकंजा कसना आसान हो जाएगा।

जनमंच में प्रस्तुत मांगों को 15 दिनों में निपटारा करने के दिए निर्देश

जनमंच में प्रस्तुत मांगों को 15 दिन में निपटाने के निर्देश

टीम रीव, सोलन

जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनमंच में प्रस्तुत मांगों और जन समस्याओं को 15 दिनों में नपटाएं। यह निर्देश जिला स्तरीय जनमंच समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य समन्वयक जनमंच एवं चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा ने दिए। उन्होंने शिक्षा, राजस्व, वन एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि विभिन्न लंबित मांगों को निपटाने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो मांगें राज्य सरकार के स्तर पर पूरी होनी हैं, उन्हें संबंधित विभागों को उचित स्तर पर भेजा जाए। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि सोलन के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विभिन्न लंबित मामलों को 10 दिन में निपटाएं। मुख्यमंत्री भी जनमंच का अनुश्रवण नियमित रूप से खुद करते हैं। वहीं नरेंद्र बरागटा ने समीक्षा बैठक शुरू होने से पहले जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौन रखकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।

लोगों की समस्या का हल करना है जनमंच का मुख्य उद्देश्य : बरागटा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने प्रथम बजट में जनमंच आरंभ करने की घोषणा की थी। जनमंच का मुख्य उद्देश्य हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में गांव–गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को उनके घरद्वार के समीप सुलझाना है। उन्होंने कहा कि जनमंच में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति जहां आम आदमी को खुलकर अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं इससे अधिकारी–कर्मचारी भी समयबद्ध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

नौ जनमंचों में उठीं सैकड़ों समस्याएं, शिकायतें सुलझाई

सोलन जिले में अभी तक नौ जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र के मटेरनी में आयोजित प्रथम जनमंच में प्राप्त सभी 138 शिकायतों

का निपटारा कर दिया गया है। सोलन विधानसभा क्षेत्र के छावशा में आयोजित दूसरे जनमंच में प्राप्त सभी 51, विधानसभा क्षेत्र के चंडी में आयोजित तीसरे जनमंच में प्राप्त सभी 92, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नंड में आयोजित चौथे जनमंच में प्राप्त सभी 142, कसौली विधानसभा क्षेत्र के गढ़खल सनावर में आयोजित पांचवें जनमंच में प्राप्त सभी 58, अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में आयोजित छठे जनमंच में प्राप्त सभी 114 और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवाग्राम में आयोजित सातवें जनमंच में प्राप्त सभी 123 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। दून विधानसभा क्षेत्र में पट्टा बारियां में आयोजित आठवें जनमंच में प्राप्त 64 शिकायतों में से 63 निपटा दी गई हैं। सोलन विधानसभा क्षेत्र के डोल का जुब्बड़ में आयोजित नौवें जनमंच में प्राप्त 29 में से 28 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष शिकायतों को भी शीघ्र निपटा दिया जाएगा।

एक ही कमरे में लग रही एक साथ पांच कक्षाएं

प्राइमरी स्कूल नेरी कलां में एक कमरे में लग रही पांच कक्षाएं

टीम रीव, सोलन

पिछले करीब सात माह से प्राथमिक विद्यालय नेरी कलां के भवन की मरम्मत की राह देख रहे ग्रामीणों ने अब विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को एक माह का अल्टीमेटम दिया है। 11 मार्च से आंदोलन की चेतावनी दी है। यहां प्राथमिक स्कूल भवन की हालत ठीक न होने का कारण माध्यमिक स्कूल से लिए एक कमरे में ही कक्षाएं लग रही हैं। इसके अलावा कार्यालय, मिड डे मील और अन्य सामान के लिए यही कमरा प्रयोग हो रहा है। इससे सर्दी के मौसम में बच्चों को एक कमरे में पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है।

स्कूल की जर्जर हालत में नहीं किया सुधार

जिले के धर्मपुर शिक्षा खंड के तहत राप्रापा नेरी कलां के भवन के छत की स्थिति जर्जर हो चुकी है। 28 जुलाई 2018 को खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपुर ने निरीक्षण किया था। स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए स्कूल की मरम्मत होने तक बच्चों को रामापा नेरी कलां में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। इस पाठशाला के शीघ्र मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इसके लिए स्वीकृति तक नहीं मिल पाई है। इस कारण जुलाई से यहां एक कमरे में पांच कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों का कहना है कि इसके कारण बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग रहा है। लोगों का कहना है कि यदि विभाग ने जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो एक

17 मार्च को आंदोलन शुरु करेंगे नेरी कलां के ग्रामीण, शिक्षा विभाग को दिया अल्टीमेटम

माह के बाद 17 मार्च को वह आंदोलन शुरू कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

शिक्षा खंड धर्मपुर के अधिकारियों के बारे में स्कूल की छत से प्लास्टर उखड़ रहा था जो बच्चों पर गिरकर उन्हें घायल कर सकता था। इसके चलते प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं लगाने के लिए मिडल स्कूल में एक कमरा लिया है। स्कूल की मरम्मत के लिए इसका एस्टिमेट तैयार कर आला अधिकारियों को भेजा था, लेकिन इसके लिए स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसमें जमीन की जमाबंदी अटैच की गई थी।

ऊना के सिंगा में मेगा फूड पार्क शुरु, किसानों को मिलेगा लाभ

टीम रीव, ऊना

ऊना जिला के सिंगा में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ बीते दिनों सासद अनुराग ठाकुर एवं हिमाचल के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने किया। लगभग एक सौ दस करोड़ के निवेश से तैयार इस मेगा फूड पार्क की स्थापना से हिमाचल और पंजाब के करीब 15 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग लाइन पर अतिरिक्त 100 करोड़ खर्च कर रही अग्रणी प्रोसेसिंग कंपनी क्रीमिका ने अपनी कार्ययोजना में क्षेत्र के करीब 15 हजार किसानों को जोड़ने की योजना बनाई है। कुल 55 एकड़ क्षेत्र में स्थापित फूड पार्क मे सालाना 15 हजार टन सब्जियों और फलों की प्रोसेसिंग होगी। यह फूड पार्क सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। भविष्य में 25 इकाइया पार्क में निवेश करेगी और 5 हजार लोगों को रोजगार हासिल होगा। इस फूड पार्क को ऊना के जिला के लोगों के लिए एक सौगात माना जा रहा है। क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके लिए किसानों और बागवानों के उत्पादों की भी यहां खपत होगी। उनको घर के पास अपनी मेहनत की अच्छी कीमत मिल जाएगी। मेगा फूड पार्क के खुलने से लोगों में खुशी की लहर है।

इस अंवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में उद्योग जगत को बढ़ावा दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फूड पार्क इसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फूड पार्क किसानों की आर्थिक तौर पर मजबूत करेगा। साथ ही इससे हिमाचल के लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आने वाले समय में फूड पार्क ऊना के विकास में भूमिका निभाएगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

देश-विदेश में फेसबुक पर लाइव होगा पालमपुर होली मेला

मेले को लेकर आयोजित बैठक में लिया फैसला

टीम रीव, कांगड़ा

पालमपुर में मनाई जाने वाली होली अब विदेशों में भी लाइव देखी जा सकेगी। राज्य स्तरीय होली को लेकर एसडीएम पालमपुर एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय होली मेला समिति पंकज शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मेला इस बार फेसबुक पर लाइव होगा। पालमपुर में 18 से 21 मार्च तक चलने वाले होली मेले के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा, सुरेंद्र ठाकुर, अरविंद शर्मा, संजय कपूर, सीमा शर्मा, अंजना सोनी, शम्मी अख्तर समेत कई मेला समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल रहे। बैठक में महोत्सव को अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए सुझाव दिए गए। एसडीएम के मुताबिक महोत्सव में हर वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए होली महोत्सव के आयोजन और महोत्सव का थीम निर्धारण के लिए आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव का लाइव प्रसारण भी फेसबुक पेज पर करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि देश-विदेश में बैठे लोग पालमपुर होली मेले को देख सकें। सांस्कृतिक संध्याओं में अन्य कलाकारों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोक सांस्कृतिक दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव में बेबी शो, डॉग शो, फ्लावर शो, फैंसी ड्रेस, महिलाओं के लिए मनोरंजक खेलों के आयोजन किया जायेगा। मेले के दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान वॉलीबाल, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, बास्केटबाल, टेबल टेनिस, चेस, कैरम बोर्ड और मैराथन का भी आयोजन होगा।

देहरा अस्पताल अपग्रेड, अब 100 से बढ़कर होंगे 150 बिस्तर

टीम रीव, कांगड़ा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देहरा के 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 150 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने हरिपुर कॉलेज में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने तथा ढलियारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उप तहसील हरिपुर को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 52 करोड़ रुपये की ब्रिकस परियोजनाएं भी देहरा क्षेत्र के लिए स्वीकृत की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद देहरा के नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा। राजकीय माध्यमिक पाठशाला खबली को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा उच्च पाठशाला बणे-दी-हट्टी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बणे-दी-हट्टी का नाम शहीद विजेंद्र सिंह रखने की भी घोषणा की। उन्होंने हरिपुर के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए उपमंडल की भी घोषणा की।

शाहपुर में बनेगा 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल

टीम रीव, कांगड़ा

स्वास्थ्य विभाग ने शाहपुर अस्पताल के 100 बिस्तरों को बनाने की अधिसूचना जारी की है। अब शाहपुर उपमंडल सहित जिला चंबा के साथ लगते क्षेत्र के हजारों लोगों को नागरिक अस्पताल में उपचार की सुविधा

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना, 26 नये पद भी सृजित

मिल पाएगी। अभी तक शाहपुर में सिर्फ 50 बेड का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल चल रहा है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सीएम जयराम ठाकुर के शाहपुर दौरे के दौरान अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी थी। सीएम ने बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 26 नए पद भी सृजित किए गए हैं।

दियोटसिद्ध में 25.50 करोड़ का बजट पास

टीम रीव, हमीरपुर

उतरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ न्यास दियोटसिद्ध की बजट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंदिर न्यास अध्यक्ष एवं एसडीएम विशाल शर्मा द्वारा की गई। बैठक में 25 करोड़ 50 लाख 88 हजार 670 का बजट प्रस्तावित किया गया। बजट में मंदिर कर्मचारियों के वेतन पर सात करोड़ 70 लाख, शिक्षण संस्थानों के वेतन पर आठ करोड़ 15 लाख, सुरक्षा कर्मियों के वेतन पर एक करोड़ प्रशासनिक वेतन पर 18 लाख, मेला अस्थायी कर्मचारी के वेतन पर आठ लाख का प्रावधान किया गया है। हिस्सेदारों के लिए 93 लाख का प्रावधान किए गया है। कुल मिलाकर 17 करोड रुपए वेतन पर खर्च होंगे। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था करने के लिए 40 लाख का प्रावधान किया गया है। आर्थिक सहायता के लिए 25 लाख ऑडिट वकील की फीस के लिए पांच लाख पूजा धूप के लिए छह लाख विद्युत बिल जनरेटर के लिए 60 लाख आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के लिए छह लाख पानी शुद्धिकरण के लिए दो लाख बच्चों के प्रावधान के लिए पांच लाख का प्रावधान किया गया है। बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास दियोटसिद्ध के अध्यक्ष एवं एसडीम विशाल शर्मा ने बताया कि 25 करोड़ 50 लाख 88 हजार 670 का बजट प्रस्तावित किया गया है। बैठक में मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल, न्यासी पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, सुरेश चौधरी, सुरेश कुमार, रमेश कुमार, पवन कुमार के अलावा अन्य ट्रस्टीयों ने बैठक में भाग लिया।

टीकाकरण पर प्रस्ताव पारित करेंगी पंचायतें

टीम रीव, ऊना

अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने हर पंचायत में बच्चों के टीकाकरण का प्रस्ताव पारित करने के आदेश दिए हैं। पंचायत यह प्रस्ताव पारित करेगी कि जन्म लेने वाले हर बच्चे का टीकाकरण होगा। उन्होंने अधिकारियों को झुग्गी-झोपड़ियों में पैदा होने वाले बच्चों का भी टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। यह बात सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है। एकीकृत बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने यह बात ऊना में कही।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का काफिला रोककर बताई समस्याएं

टीम रीव, बिलासपुर

बीते दिनों सड़क की खस्ताहालत को लेकर सामाजिक संस्था ग्लोबल ज्यूरिस्ट ने ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री का काफिला रोका दिया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने सीएम को समस्याएं सुनाई। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को स्वयं सड़क पर उतरकर सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल उनकी समस्याओं को हल करने के आदेश जारी किए। ग्लोबल ज्यूरिस्ट संस्था ने सीएम जयराम ठाकुर का काफिला उस समय उन गड्ढों के पास रोक दिया, जब वह जुखाला में करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद विभाग ने इन गड्ढों को रातों-रात मिट्टी व रेत से भर दिया था जिसको लेकर स्थानीय लोगों व संस्था के अधिकारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से इसका स्थायी समाधान करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का किया शुभारम्भ

टीम रीव, कांगड़ा

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले राज्य के लगभग 8,42,600 किसानों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2018 और जनवरी व फरवरी, 2019 के महीने के लिए 2000 रुपये की पहली किस्त प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राज्य के 1,41,677 किसानों के खातों में जमा की जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत होते ही शेष किसानों को भी यह राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता की दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमान्त किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा यह योजना किसानों को 6,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों को उनके खातों में तीन किश्तों में 2,000 रुपये की प्रत्येक किश्त के रूप में प्रदान की जाएगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता तीन समान किश्तों में लघु एवं सीमांत किसानों के परिवारों को प्रदान की जाएगी। जिनके पास दो हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरित करने के लिए योजना 1 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के 12.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली चार महीने की अवधि के लिए पहली किश्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थी को एक और मुफ्त गैस रिफिल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना में 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जा रहा है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भी प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल किसानों के लिए ज्यादा आय सुनिश्चित करेगा बल्कि जनता को स्वस्थ भोजन भी प्रदान करेगा।पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है, जो किसानों को उनकी कृषि आय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में किसी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा दूरदर्शी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने प्रदेश में इस योजना के शुभारम्भ के लिए कांगड़ा जिले को चुनने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

केन्द्रीय मंत्री ने किए 4500 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्गों के शिलान्यास

टीम रीव, कांगड़ा

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में कांगड़ा जिले के गग्गल में बीते दिनों 4459.24 करोड़ रुपये की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के तहत 1572.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पंजाब-हिमाचल सीमा से सिहुणी खण्ड के 37.05 किलोमीटर के फोर लेनिंग कार्य का शिलान्यास किया। केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के तहत 1356 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 104.60 किलोमीटर के पांवटा साहिब गुम्मा-फेडुजपुल खण्ड के कार्य की आधारशिला भी रखी। नितिन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के तहत 1,334 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हमीरपुर-मंडी खण्ड के 109.75 किलोमीटर के कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 503ए के तहत 51.09 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 15.75 किलोमीटर के ऊना-भीरू खण्ड के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के तहत 46.13 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 23.10 किलोमीटर के मटौर-धर्मशाला-मैकलोडगंज खण्ड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के तहत 30 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सात किलोमीटर के पांवटा साहिब टाऊन खण्ड का शिलान्यास किया। केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के तहत 29.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 94 किलोमीटर के सैंज-लुहरी-आनी जलोड़ी-बंजार-ऑट खण्ड के बीच रिटेनिंग वॉल और क्रैश बैरियर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 40.05 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 49 किलोमीटर की बारोह चौक-देहरीयां-जंदराह-टाली-लगरू-डोला खुडिंया-नाहलियां सड़क का भी शिलान्यास किया।

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।
द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334, Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

देवदार के 70 स्लीपर; कटा पेड़ बरामद, बीओ और फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड

टीम रीव, कुल्लू

वन मंत्री के गृह जिले कुल्लू में अवैध कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उपमंडल बंजार की ग्राम पंचायत बाहू की शिकारी बीट में वन काटुओं से देवदार के करीब 70 स्लीपर, दो लॉग और एक कटा हुए पेड़ बरामद हुआ है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई अमल में लाई है। इस मामले में सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ड्यूटी में कोताही बरतने पर डीएफओ ने कार्रवाई करते हुए बीओ और शिकारी बीट के फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। अवैध कटान के बड़े मामले को लेकर अब बंजार में हड़कंप मच गया है। डीएफओ प्रवीण ठाकुर की अगुवाई में शनिवार देर शाम टीम शिकारी बीट में पहुंची। टीम ने अवैध कटान करने वाले एक गिरोह को दबोचा। मौके से चमन लाल, रमेश, ध्यान सिंह, चंद्र, तारा चंद, अमीर चंद को गिरफ्तार कर किया, जबकि नवीन कुमार उर्फ नोखू, निवासी बाहू मौके से भागने में कामयाब रहा। लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। मौके पर पकड़ी गई संपत्ति की कीमत 6 लाख 56,849 बताई जा रही है। वन विभाग अभी भी कुछ जगहों पर छापामारी करने में जुटा है। अब कुछ और वन काटु भी पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं।

धर्मपुर को बस डिपो–संधोल को सब–डिपो

टीम रीव, मंडी

वन एवं परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने धर्मपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के डिपो तथा संधोल में स्थापित होने वाले उपडिपो का शुभारंभ किया। उन्होंने धर्मपुर से धर्मशाला के लिए बस सेवा का भी शुभारंभ कर उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकाघाट के समीप बरच्छवाड़ में परिवहन निगम की कार्यशाला तथा पपलोग में चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण भी किया। धर्मपुर में गोबिंद ठाकुर ने कहा कि डिपो व सब डिपो के आरंभ होने से लोगों को परिवहन की और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। परिवहन निगम के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। जिला में भी पायलट आधार पर चुनिंदा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। धर्मपुर से दिल्ली के लिए भी एक नई बस सेवा प्रारंभ की गई है। धर्मपुर व मंडप में स्टेडियम निर्माण के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटी में खेल मैदान का प्राक्कलन तैयार करने को भी कहा। धर्मपुर क्षेत्र में स्थित वन विभाग के विश्रामगृहों का चरणबद्ध ढंग से नवीनीकरण किया जाएगा। धर्मपुर में प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री रजत ठाकुर ने गोबिंद ठाकुर का स्वागत किया। वन मंत्री ने धर्मपुर में आयोजित तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का समापन भी किया। इससे पूर्व पपलोग में गोबिंद ठाकुर ने कहा कि बरच्छवाड़ में बस अड्डा व परिवहन निगम की कार्यशाला के निर्माण के लिए सरकार बजट का समुचित प्रावधान करेगी। पपलोग में चालक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने पपलोग में निर्मित होने वाले खेल स्टेडियम का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोलथरा में बास्केटबॉल फील्ड के लिए पांच लाख, राजकीय उच्च पाठशाला रसैण गलू में बैडमिंटन कोर्ट के लिए पांच लाख, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सधोट में स्टेज निर्माण के लिए पांच लाख, राजकीय उच्च पाठशाला कांगू का गहरा में स्टेज निर्माण तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला सरौन में चारदीवारी के लिए पांच–पांच लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

टीपरीबीड़ पहाड़ी में दरारें, फगवाणा गांव को खतरा

टीम रीव, कुल्लू

जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत चकुरठा के गांव फगवाणा को पहाड़ी से खतरा हो गया है। पहाड़ी के खतरे से गांव में रह रहे 150 से अधिक परिवारों की रातों की नींद व दिन का चैन हराम हो गया है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि टीपरीबीड़ पहाड़ी में बड़ी–बड़ी दरारें आ गई हैं और पहाड़ी खिसकना शुरू हो गई है। यदि पहाड़ी गिर गई तो पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा और भारी तबाही मचेगी। गौर रहे कि गांव के ऊपर टीपरीबीड़ नामक पहाड़ है और पहाड़ी पर लोगों की जमीनें भी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ी में दरारें आ गई हैं। अब यह दरारें गहरी होती जा रही हैं और खतरे का निशान बढ़ गया है। पहाड़ी के नीचे पूरा गांव बसा हुआ है और 150 से अधिक मकान हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पहाड़ी खिसकी तो सिर्फ फगवाणा गांव ही नहीं दबेगा, बल्कि यहां से नीचे वाले गांव ओड़ी धार व नाउली आदि को भी भारी नुकसान होगा। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन व सरकार से गुहार लगाई है कि शीघ्र जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से यहां का सर्वे करवाया जाए और पहाड़ी से बचने का कोई तरीका तलाशा जाए, ताकि गांव के सैकड़ों लोगों की जान बच सके और भारी नुकसान को रोका जा सके। गांव के लोगों ने पहाड़ी पर जाकर जायजा लिया और देखा कि खतरा बढ़ गया है। बहरहाल गांव को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे अन्यथा बहुत बड़ी घटना घट सकती है।

वन मंत्री ने लिया प्रभावित क्षेत्रों का जायजा

विभाग को जल्द सड़कें बहाल करने के दिए निर्देश

टीम रीव, कुल्लू

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बीते दिनों कुल्लू में भारी बारिश के कारण प्रभावित स्थलों का दौरा किया। वह 15 मील तथा बाशिंग बाढ़ग्रस्त स्थानों में पहुंचे और राहत व बहाली के कार्यों का जायजा लिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि जिले में पिछले दिनों हुई लगातार वर्षा व बर्फबारी के कारण अनेकों सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग को सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अनेक स्थानों पर लोगों के घरों में मलबा आ गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बहाली के कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर बिजली व पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में तेजी से प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि मौसम लगातार खराब चल रहा है, लेकिन बहाली के कार्य भी रुकने नहीं चाहिए और लोगों को राहत पहुंचनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग कुल्लू–मनाली पर पर्याप्त मशीनरी तैनात करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने बहाली के कार्यों में जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जहां कहीं से भी स्थानीय तौर पर सड़क, बिजली व पानी के अवरोध की सूचना प्राप्त हो रही है, तुरंत से कार्रवाई करते हुए बहाली के

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चंबा ने शुरु किए प्रयास, मिलेगी लोगों को राहत

निरीक्षकों को दिए आदेश, ज्यादा हिमपात वाली पंचायतों को करें चिन्हित

टीम रीव, चंबा

जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्रों के अलावा अब ऐसी पंचायतों में भी राशन की पहले से व्यवस्था करवाई जाएगी, जहां भारी हिमपात होता हो। इस संदर्भ में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चंबा की ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। विभाग ने जिला के समस्त निरीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्रों की सूची उपलब्ध करवाएं। जैसे ही कार्यालय यह सूची पहुंचेगी, विभाग की ओर से इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की स्वीकृति मिलते ही इन क्षेत्रों में एडवांस में राशन की व्यवस्था आगामी सर्दियों के सीजन को लेकर की जाएगी। विभाग की ओर से इस तरह का प्रयास करने का मकसद दूरदराज के क्षेत्रों के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है। ताकि बर्फबारी के दौरान उन्हें खाद्य पदार्थों की परेशानी न हो। इस साल जिला में भारी हिमपात हुआ है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों के लिए पहले से ही राशन को एडवांस में भेजने की व्यवस्था है, लेकिन जिला की कई पंचायतें ऐसी है जिन्हें जनजातीय दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में यहां राशन की व्यवस्था हर माह की जाती है। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने के कारण यहां सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता। इसके चलते राशन कार्ड उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विभाग ने इस मामले को लेकर सकारात्मक पहल करते हुए दुर्गम क्षेत्रों में भी राशन का एडवांस कोटा भेजने का प्रपोजल सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक जिला के समस्त निरीक्षकों से ऐसे क्षेत्रों (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर)की सूची मांगी गई है जहां हिमपात काफी हुआ है। सूची मिलते ही इसे सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आगामी सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले एडवांस

32 साल बाद बदला व्यापार मंडल का प्रधान

टीम रीव, मंडी

मंडी की बीबीएमबी कालोनी सुंदरनगर के सर्वसम्मति से हुए चुनावों में अश्वनी सैणी को व्यापार मंडल का प्रधान चुना गया। गौरतलब है कि पुलिस पहरे में 32 वर्षों के बाद बीबीएमबी कालोनी सुंदरनगर के सर्वसम्मति से हुए चुनावों में अश्वनी सैणी को व्यापार मंडल का प्रधान चुना गया। हालांकि पूर्व प्रधान के दो समर्थकों ने वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन उपस्थित सैकड़ों दुकानदारों ने एक आवाज में अश्वनी सैणी का समर्थन किया और उन्हें हार पहनाकर अपना प्रधान घोषित किया। हरचरण दास पिछले 32 वर्षों से प्रधान पद पर काबिज थे। इससे पूर्व बीबीएमबी कालोनी व्यापार मंडल के प्रथम चुनाव 21 फरवरी 2010 में काफी तनावपूर्ण माहौल में हुए थे, जिसमें मौजूदा अध्यक्ष अश्वनी सैणी हरचरण दास से 29 वोटों के मुकाबले पिछड़ गए थे। इंदिरा मार्केट के पार्किंग ग्राउंड में स्थानीय पार्षद पुष्पा व तुनाही महिला मंडल प्रधान नीलम की अध्यक्षता में संपन्न हुए चुनाव में पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बंदोबस्त किए थे और इस दौरान थाना प्रभारी सहित तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस व महिला कर्मी मौजूद रहे।

परंपरागत कूहलों के बजाय टपक सिंचाई योजना अपनाएं

आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में कृषि–बागवानी के क्षेत्र में दीर्घकालीन योजनाएं बनाने तथा समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों–बागवानों से परंपरागत कूहलों के बजाय टपक व फव्वारा सिंचाई योजना को अपनाने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में इजरायल में की जा रही बागवानी तकनीकों की जानकारी भी बागवानों से साझा की। महेंद्र सिंह ने बताया कि बागवानी विकास के लिए 1688 करोड़ की परियोजना के तहत कलस्टर बनाए जाएंगे तथा इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। आसमान से बरसने वाली एक–एक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 1134 करोड़ की एक अन्य योजना के माध्यम से सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। खुंब उत्पादन के लिए भी 423 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।

खराहल, मणिकर्ण को मिली 12.66 करोड़ की सौगात

टीम रीव, कुल्लू

आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की खराहल और मणिकर्ण घाटी में लगभग 12 करोड़ 66 लाख रुपये की पेयजल व सिंचाई योजनाओं के शिलान्यास किए। उन्होंने शाट में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल का उद्घाटन भी किया। बारी–पधरू, बालू–रा–घेरा और कशादा में जनसभाओं को भी संबोधित किया। महेंद्र सिंह ने सबसे पहले खराहल के बारी–पधरू में 3 करोड़ 67 लाख की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना खराहल के कमान क्षेत्र के विस्तार की आधारशिला रखी। इस योजना से घाटी की पांच पंचायतों के लगभग 800 किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके बाद महेंद्र सिंह ने मणिकर्ण घाटी के बालू–रा–घेरा में लगभग एक करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इस योजना से क्षेत्र की 16 बस्तियों के चार हजार से अधिक लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का काम एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। गांव फागू के लिए भी एक पेयजल योजना की डीपीआर तैयार की जाएगी। मणिकर्ण के शाट में नए उपमंडल का उद्घाटन और उठाऊ सिंचाई योजना फाटी चौंग का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि फाटी चौंग सिंचाई योजना पर एक करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। महेंद्र सिंह ने कहा कि शॉट में विभाग का उपमंडल खुलने से मणिकर्ण घाटी में पेयजल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के निर्माण को गति मिलेगी तथा इन योजनाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित होगा। आईपीएच मंत्री ने बगियांदा में 6 करोड़ 10 लाख की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना जरी–बराधा का शिलान्यास भी किया।

चूड़ी और लोथल को लोगों को मुफ्त मिले बिजली

टीम रीव, चंबा

ग्राम पंचायत लोथल के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त चंबा हरीकेश मीणा से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ग्रामीणों ने चमेरा चरण तीन परियोजना में प्रभावित ग्राम पंचायत लोथल के गांव चूड़ी और लोथल को परियोजना की तरफ से मुफ्त बिजली देने मांग उपायुक्त के समक्ष रखी। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे संजय राजपूत ने कहा कि ग्राम पंचायत लोथल का गांव चूड़ी और लोथल एनएचपीसी चमेरा चरण–तीन परियोजना में पूरी तरह प्रभावित गांव है। परियोजना के सभी कार्यालय इन्हीं गांव में बने हैं। एनएचपीसी चमेरा चरण–तीन परियोजना के कार्यालय में ही बिजली होती है जबकि अन्य स्थानों पर अंधेरा पसरा रहता है। जिस क्षेत्र में बिजली

लोगों ने उठाई मांग

पैदा हो रही है वही क्षेत्र अंधेरे में डूबे हैं जो किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। इसलिए ग्रामीणों ने जिलाधीश से मांग की है कि उपरोक्त परियोजना प्रबंधन को निर्देश जारी कर गांवों में मुफ्त बिजली मुहैया करवाई जाए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कानून-व्यवस्था को जानिए क्या है कानून व्यवस्था

किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। अक्सर जहां भी कहीं राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव होता है, या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है । यानी किसी क्षेत्र में अशांति या हिंसा होना भी कानून व्यवस्था का सकंट ही होता है।

कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी

भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून अधिनियमित करता है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रख-रखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग पुलिस बल है। राज्यों की पुलिस के पास ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है।

कानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं । अपराध रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच-पड़ताल करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और खासकर पुलिस को दी गई है । संविधान के मुताबिक ही केन्द्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण, अस्त्र-शस्त्र, संचार, उपस्कर, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

एनसीआरबी है मददगार

कानून व्यवस्था और अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा और सूचना एजेंसियां राज्य की कानून और प्रवर्तन इकाईयों को नियमित रूप से जानकारी देती हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, जो अपराधों को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्यों की सहायता करती है । और राज्यों को अपराध संबंधी आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करती है ।

सीसीआईएस भी है सहायक

अपराध अपराधी सूचना प्रणाली (सीसीआईएस) के तहत देश के सभी जिलों में जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (डीसीआरबी) और राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) को कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ा गया है । यह प्रणाली अपराध रोकने, उनका पता लगाने और सेवा प्रदाता तंत्रों में सुधार करने में सहायक है । इसकी मदद के पुलिस और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां अपराधों, अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्ति का राष्ट्र स्तरीय डाटाबेस रखती हैं ।

कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी ओसीआईएस

एनसीआरबी के दिशा निर्देश में संगठित अपराध के ख़तरे से प्रभावी ढंग से निपटने के मकसद से एक और नई प्रणाली स्थापित की जा रही है । जिसे संगठित अपराध सूचना प्रणाली यानी ओसीआईएस का नाम दिया गया है । इसके तहत विभिन्न अपराधों से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध होंगे जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक साबित होंगे ।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

स्वाइन फ्लू: लक्षण, रोकथाम और बचाव

स्वाइन फ्लू क्या है?

H1N1 इन्फ्ल्यूएंजा या स्वाइन फ्लू दरअसल चार वायरस के संयोजन के कारण होता है। आम तौर पर इस वायरस के वाहक सूअर होते हैं। यही वजह है कि मीडिया ने इसे स्वाइन फ्लू यानि कि 'सुअर फ्लू' का नाम दे डाला। अब तक यह जानवरों के लिए घातक नहीं था और न ही कभी इसने इंसानों को प्रभावित किया था।

इस फ्लू ने महामारी के रूप धारण कर लिया है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल रहा है। जोखिम का विषय यह है कि एक नया वायरस स्ट्रीम बन जाने के कारण कोई भी इससे अप्रभावित नहीं है। लिहाजा प्रत्येक व्यक्ति इस संक्रमण के प्रति संवेदनशील है।

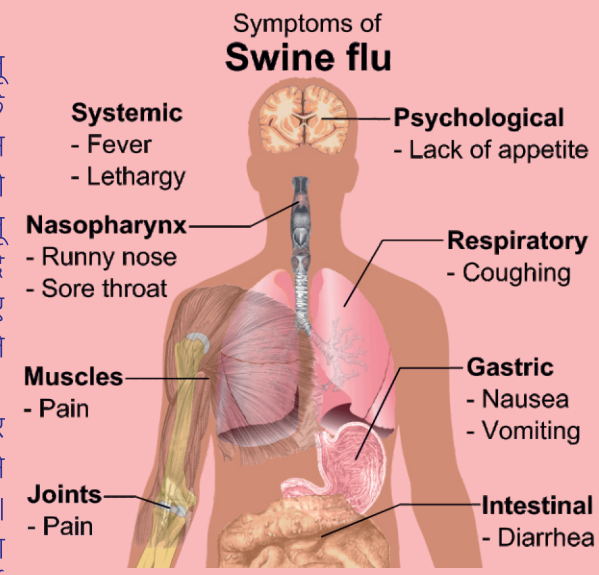

लक्षण

हालांकि इसके लक्षण एक सामान्य फ्लू के समान हैं, मगर लापरवाही बरतने पर वे गंभीर हो सकते हैं। आम तौर पर इन लक्षणों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।

बुखार,
खाँसी, सिरदर्द,
कमजोरी और थकान,
मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द,
गले में खराश,
नाक बहना

बचाव और बीमारी की रोकथाम के उपाय

- खांसी अथवा छींक के समय अपने चेहरे को टिश्यू पेपर से ढककर रखें ।
- टिश्यू पेपर को सही तरीके से फेंके अथवा नष्ट कर दें।
- अपने हाथों को किसी हैंड सैनीटाइजर द्वारा नियमित साफ करें।
- अपने आसपास हमेशा सफाई रखें।

चेहरे पर मास्क को बचाव का एक तरीका माना जा रहा है, मगर वास्तव में यह कितना प्रभावी है इस बारे में किसी रिसर्च के जरिए कोई पक्के नतीजे सामने नहीं आए हैं।

आपको क्या करना है

यदि आपको फ्लू के लक्षण महसूस हो रहे हैं, भले ही आपने हाल में कोई यात्रा की हो या नहीं, तुरंत डाक्टर के पास जाएं। यदि टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लू का एंटीवायरल ड्रग टैमीफ्लू के जरिए इलाज किया जा सकता है।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

दुनिया में पहली बार यहां उगा था लौंग का पेड़, 3 हजार साल पुराना है इतिहास

द रीव टाइम्स ब्यूरो :लौंग का इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा, या तो मसाले के रूप में या दांत में दर्द होने पर। इस मसाले का उपयोग भारतीय खानों में बहुत किया जाता है। आज भले ही लौंग दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में पहली बार लौंग का पेड़ कहां उगा था? इसका एक लंबा इतिहास है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आज से करीब तीन हजार साल पहले लौंग का पेड़ सिर्फ पूर्वी एशिया के कुछ द्वीपों पर ही हुआ करता था। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के टर्नेट द्वीप पर दुनिया का सबसे पुराना लौंग का पेड़ है। टर्नेट द्वीप के ज्यादातर हिस्से में ज्वालामुखी हैं, लेकिन फिर भी यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं । बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 3-4 हजार साल पहले टर्नेट, टिडोर और उसके आस-पास के कुछ द्वीपों पर लौंग के पेड़ पाए जाते थे। लौंग का कारोबार करके इन द्वीपों पर रहने लोग उस समय काफी अमीर हो गए थे। कहते हैं कि जब टर्नेट और टिडोर के सुल्तानों के पास लौंग के कारोबार से काफी दौलत आ गई, तो वो खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझने लगे और आपस में ही लड़ने लगे। इस बात का फायदा उठाकर अंग्रेज और डच कारोबारियों ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां भारी मात्रा में लौंग पाए जाते थे। कई सालों तक ये द्वीप यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं। इन द्वीपों पर कई तरह के जीव-जंतु भी पाए जाते हैं। यहां उड़ने वाले मेंढक भी पाए जाते हैं। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने नई नस्लों की खोज में इन द्वीपों पर कई साल बिताया था। साल 1862 में जब वो वापस लंदन चले गए, वो अपने साथ करीब सवा लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के नमूने लेकर गए थे। आज उन्हीं की वजह से हमें जानवरों की कई सारी नस्लों के बारे में जानकारी मिली है।

साभार : ऑन लाइन

ये क्रिकेट की नहीं राष्ट्रीय पिच है.....अधिक उछाल घातक ही होती है

इमरान पाकिस्तान के हित पर आतंकवाद को तवज्ज़ो न दें

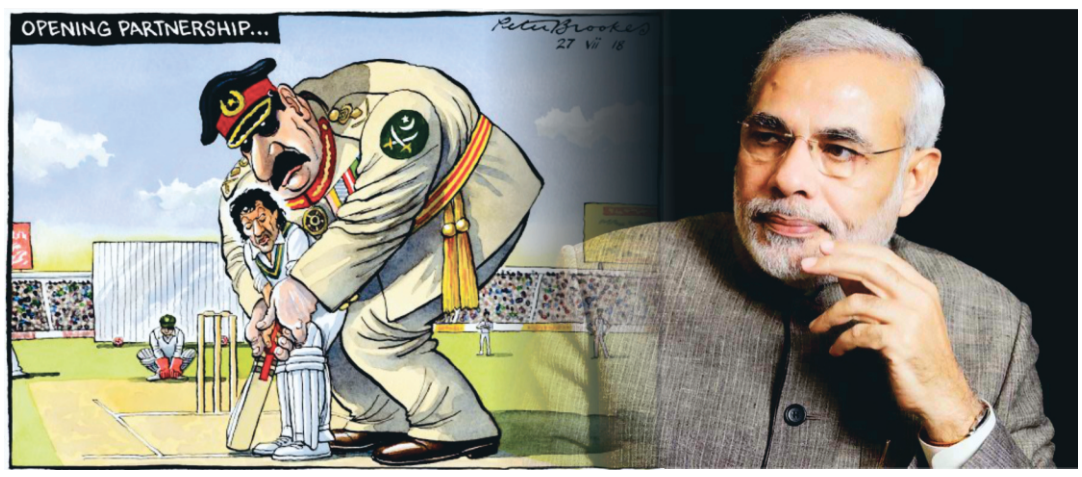

किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व उसकी दिशा को तय करता है। संतुलित विकास और सुरक्षा की जिम्मेवारी एक राष्ट्र का ध्येय होता है। बचकाना और अपरिपक्कव निर्णय कभी–कभी राष्ट्र के लिए घातक हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ वर्तमान में कुछ ऐसा ही दृश्य घटित हो रहा है। नए प्रधानमंत्री इमरान खान की अपरिपक्वता और नासमझी से आज पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबतें उत्पन्न हो गई है। लेकिन इस राजनैतिक अनुभवहीनता और ग़लती से भारत और पाकिस्तान दोनों ही नुकसान तो झेलेंगे ही। यहां दीगर बात यह है कि भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध इस बार बेहद कड़ा रुख़ अपनाया है, और लगता नहीं कि अब आर–पार की लड़ाई में आतंकवाद पर कोई समझौता होने वाला है, और यदि इस कठिन समय में भी आतंक को दरकिनार कर लचीलापन अपनाया गया तो यह एक लाइलाज़ नासूर बन जाएगा जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ीयों को भुगतना पड़ेगा।

भारत के भीतर ही षड़यंत्र रच कर सरहद पार से आतंक के आकाओं का खूनी खेल हो रहा है और पाकिस्तान उनको गोदी में छुपाने के लिए आतुर हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं इमरान खान ने अधिकारिक तौर पर भारत को अपने डर के कारण कह दिया कि अगर भारत ने पुलवामा के बाद पाकिस्तान के साथ कुछ भी ग़लत करने की सोची तो पाकिस्तान रिटालियट करने की सोचेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान रिटालियट करेगा। आख़िर परिणाम में वही हुआ भी। भारत का सर्जिकल प्रहार पाकिस्तान को अंदर तक तोड़ गया। पाकिस्तान में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई। लेकिन प्रतिउत्तर में पाकिस्तान ने जब जवाब देना चाहा तो हमारे लड़ाकु जहाजों ने उन्हें ऐसा करने से सीमा पर ही रोक दिया जिसमें भारत के एक जाबांज़ पायलट अभिनंदन घायल होकर पाकिस्तान की आर्मी की गिरफ्त में आ गए। सोशल मीडिया में आई क्लिप्स में पहले तो वहां के लोगों ने जाबांज़ के साथ अमानवीयता की और फिर पाक की आर्मी का भी एक विडियो आया जिसमें पुछताछ हो रही है और अभिनंदन ने बडी ही जांबाज़ी के साथ अपना देशभक्तिपूर्ण उत्तर दिया।

यहां ग़ौर करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसे भी भुनाना चाहते हैं और बातचीत के लिए भारत के आगे भीख मांग रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें जिनेवा कन्वेंशन नियमों को पता होते हुए भी एक हास्य कलाकार की भूमिका में ही देश चलाने का निर्णय कर लिया हैं। युद्ध के दौरान यदि किसी भी देश का जवान बंदी बनाया जाता है तो उसे एक तय सीमा के अंदर सकुशल छोड़ना पड़ता है। उसके साथ न तो कोई अमानवीय व्यवहार होगा और न ही किसी भी प्रकार का टार्चर किया जाएगा। अब पाकिस्तान के गले में यह हड्डी फंसने की तरह हो गया। पायलट को आगे कर बातचीत या समझौता करने की नीति इस बार भारत मानने से स्पष्ट मुकर गया। यानि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा।

पाकिस्तान कितने ही हथकंडे अपनाऐगा डर और भारत की कार्यवाही से बचने के लिए ? लेकिन आतंकवाद पर सख़्त कार्यवाही करने से हमेशा मुकरता रहेगा। मसूद और जैश–ए–मुहम्मद पर कार्यवाही नहीं करेगा चाहे इसके लिए पूरा पाकिस्तान की आवाम की बलि देनी पड़े। इमरान खान इसे क्रिकेट की पिच मान कर चल रहे हैं कि एक बॉल छूट गई तो दूसरी बॉल का इंतज़ार करें। यह राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता का प्रश्न है..। कश्मीर को रक्तरंजित करने और भारत की अखंडता को नुकसान करने की मंशा पाले इमरान खान पाकिस्तान को रणनीतिक गड्ढे में डाल चुके हैं। भारत की कार्यवाही पर जहां पूरे विश्व का समर्थन केवल इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि यह लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान में जड़ें जमाए उस आतंकवाद के ख़िलाफ है जिसे पाकिस्तान सींच रहा है।

इमरान खान को समझना होगा कि विश्व आज विकास की जिस उड़ान पर दौड़ रहा है उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक पाता है। भारत भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और तकनीकि में विश्व को टक्कर दे रहा है। वहीं, पाकिस्तान आतंक की फसलें उगा रहा है, उसे सींच रहा है और उसके विस्फोटक फल भारत के अलावा अन्य देशों में भी बांट रहा है। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही एक उम्मीद विश्व के बुद्धिजीवियों में चर्चा का विषय बनी थी कि अब पाकिस्तान को एक सही नेतृत्व मिल सकता है लेकिन हालात बद् से बद्तर होते गए। अभी इमरान खान को जुम्मा–जुम्मा चार दिन वज़ीर–ए–आज़म बने नहीं हुए और अकड़ व हेकड़ी में पाकिस्तान की आज विश्वभर में किरकिरी करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन भारत अब वापिस आने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि ऐसा पहली बार है कि पूरा देश कश्मीर, आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सीखाने की ठान चुका है और ये तो इमरान भलिभांति से जानते है कि भारत के जवान कुछ ठान लें तो 1965, 1971, 1999 कारगिल, सर्जिकल स्ट्राईक पार्ट 1 और पार्ट 2 को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान की आवाम भी आतंकवाद से छुटकारा पाना चाहती है। ब्लूचीस्तान भी पाकिस्तान की आर्मी और आतंकियों से बेचैन हो चुकी है। इसे इमरान को मानवता के नाते समझना आवश्यक है। भारत के लिए तो अब समझना या न समझना धर्मयुद्ध की कसौटी बन गया है जिसमें आतंक की आहूति के साथ ही यज्ञ पूर्ण होगा।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

वीर भारत तुम बढ़े चलो....

आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध छेड़ने का वक्त

'हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे
ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।'

महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित कविता की ये पंक्तियां यूं तो प्राथमिक स्तर पर सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन आज इन पंक्तियों के मायने और भी अधिक हो जाते हैं। आज ये पंक्तियां हर भारतीय के मन में गीत बनकर गूंज रही है क्योंकि सीमा पर युद्ध जैसी या यूं कहें कि युद्ध की स्थिति है। पुलवामा हमले के बाद वीर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो ध्वजा उठाई है उससे दूसरे देश भी भारत का लोहा मान रहे हैं। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद जिस तरह तेरहवें दिन 26 फरवरी को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई उसकी पूरे विश्व में सराहना की गई। लेकिन मसला सराहना भर से हल होने वाला नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जो ध्वजा भारत ने उठाई है अब उसे झुकने न देना सभी देशों की जिम्मेदारी है। यानि आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एक जुट होना होगा। भारत पर आतंक का डंक बहुत गहरा है लेकिन यह भी सच है कि आज कोई भी देश आतंक की समस्या से अछूता नही हैं। साफ है आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध छेड़ने का वक्त आ गया है। भारत में 14/2 का पुलवामा, मुंबई में 26/11, अमरीका के न्यूयार्क में 9/11, लंदन के 7/7 और अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13/11 और ईरान में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भी क्या सोचना शेष है?

आतंकी हमले तो कई हैं, लेकिन ऐसे कुछ हमले हुए हैं, जिन्हें तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बांधने वाला समझा जाता है। इन सब के बीच यह भी पहले से रेखांकित है कि आज युद्ध हुआ तो वह महाविनाशक होगा। आत्मरक्षा के नाम पर संजोए गए परमाणु हथियार किसके रक्षक होंगे और किसके भक्षक, कहना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है कि धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ सभी देश

ईमानदारी से लड़ाई लड़े। विभिन्न देशों के मसलों को उठाने के लिए सबसे बड़े मंच माने जाने वाले संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा, रणनीति, कूटनीति आदि तो बाद में भी तय हो सकती है,लेकिन सबसे पहले मौजूदा स्थिति का जवाब देना अहम और जरूरी है। आतंकवाद आज अकेले भारत की समस्या नहीं है बल्कि आतंकवाद ने बड़े देशों के अहंकार, उनकी चौधर, दादागीरी पर भी बड़े हमले किए हैं। खुद को महफूज मानने वाले अमरीका और यूरोप के देश अब आतंकवाद से घिरे हैं। कहीं भी, किसी भी दिन आतंकी हमला संभव है। स्पष्ट है कि वीर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो ध्वजा बुलंद की है उसे ऊंचा रखना आज सभी देशों की जरूरत और कर्त्वय दोनों है।

आतंकवाद पर देशों को साथ लेने के लिए भारत ने जो कोशिश की वह सराहनीय है। पाकिस्तान– चीन की जगजाहिर नदीकियों के बीच जिस तरह भारत की विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने चीन जाकर बैठक में पुलवामा हमले की निंदा के बाद भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाने के लिए की गई एयर स्ट्राइक को सही ठहराया, उससे चीन भी पसोपेश में आ गया। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद चीन ने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान को चीन का समर्थन नहीं मिला है। इसके बावजूद अभी भी आतंकी सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन का रूख संदेहास्पद है। जाहिर है बयानबाजी और हकीकत में आतंकवाद को पनाह दे रहे पाकिस्तान के खिलाफ जाने के लिए चीन को रणनीतिक और राजनीतिक दोनों तरह की इच्छाशक्ति दिखानी होगी। लेकिन जिस तरह पिछले एक दशक से चीन पाकिस्तान का दोस्त बनकर अपने हित साधने में लगा है, उससे चीन पर बहुत ज्यादा विश्वास करना मुश्किल है। बात यह भी है कि चीन के अपने हित पाकिस्तान से जुड़े हैं।

दरअसल चीन कई कारणों से पूरी तरह पाकिस्तान की आर्मी पर निर्भर है, इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण चीन–पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के काम में लगे चीनी नागरिकों की सुरक्षा भी है। एक अंदाजा है कि पाकिस्तान में चीन के करीब 60 हजार लोग हैं। चीन भी आतंकवाद से अच्छूता नहीं है। चीन इस समय शिंजियांग में अलगाववादियों की समस्याओं से जूझ रहा है। कहा जाता है कि शिजियांग के अलगाववादियों को पाकिस्तान और अफगानीस्तान आधारित संगठनों का सहयोग मिलता है। ऐसे में चीन पाकिस्तानी सेना का सहयोग चाहता है ताकि अलगाववादियों को पाकिस्तान से सहयोग न मिले। एक बड़ी बात यह भी है कि भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन मुस्लिम देश के तौर पर भी पाक का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में भारत के साथ साथ दुनिया के बाकि देशों को भी समझना होगा कि वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ किसका चेहरा कितना साफ है। हालांकि भारत के आक्रामक रूख के बाद फ्रांस, अमेरिका, रूस और अन्य महाशक्तियों ने जिस तरह पाकिस्तान पर आंखे तरेरी है उससे यह उम्मीद जरूर जगी है कि शायद आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान सरीखे देश कुछ सुधार करेंगे।

अंजना ठाकुर
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स

पुलवामा से वोट तक...देश समाधान चाहता है

लाशों पर कब तक स्वार्थ के महल बनेंगे

आर या पार की जंग में आतंक का साम्राज्य ख़त्म हो

एक लंबा अरसा पहले बुजुर्ग बताते हैं कि कश्मीर का नाम ज़हन में आते ही स्वर्ग से सुंदर दृश्य, ज़न्नत की ख़्वाबगाह, पानी पर तैरते घर, झील में तैरता शिकारा.....आया करता था जिसकी पूरी क़ायनात क़ायल थी । मनुष्य ने अपना ऐसा रुप बदला कि सत्ता की स्वार्थसिद्धि में ज़न्नत धीरे–धीरे ज़हन्नुम बनती गई और आज कश्मीर का ज़िक्र होते ही बंदूकें, दंगे, फसाद, आतंक, खून–ख़राबा, आगजनी, पथराव, लाशें ...बस यही सब पहली नज़र में दिखाई देता है । कभी–कभी तो लगता है कि अपने ही घर में रहने के लिए अपनों से ही जंग लड़ी जा रही है । क्या आज़ादी से पहले ही इस समस्या को जानबूझ कर खुले ज़ख़्मों से लबरेज़ छोड़ दिया गया था ? क्या आज़ाद भारत की नींव कहीं न कहीं कश्मीर समस्या के साथ ही रखी गई थी ? क्या आज़ादी के बाद 72 वर्षों में इतने बड़े लोकतंत्र से यह समस्या न सुलझ पायी ? ये कुछ प्रश्न है जो प्रत्येक भारतवासियों को बार–बार कचोटते हैं ।

पुलवामा फिदायनी हमला.....अब बर्दाश्त से बाहर

आज़ादी के बाद के कश्मीर में हुयी सभी आतंकवादी घटनाओं में पुलवामा ने भी बेहद दुखद और भयानक तरीके से दस्तक दी है । भारतीय जवानों की बस पर फिदायन हमला केवल हमारे जवानों को ही शहादत नहीं दे गया बल्कि उनके पीछे पूरा परिवार और देश इस घटना पर दुःखी और स्तब्ध है । देश हमारा, कश्मीर हमारा, लोग हमारे, गाड़ी हमारी फिर भी किसी को कानोंकान ख़बर नहीं .....और 300 किलो. आरडीएक्स से जवानों को चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं । बारुद का इतना असला कहां से आया, किसने आने दिया, जवानों की पल–पल की ख़बर कैसे फिदायनियों को मिलती रही.. .ये सब अभी भी सरकार के लिए यक्ष प्रश्न हो सकते हैं लेकिन भारतवासियों के लिए यह समझना अब आसान होता जा रहा है कि कहीं न कहीं लंका को ढहाने की साजिश घर के विभिषण ने ही की है । पुलवामा में जो हुआ उसे लेखनी से कागज़ पर उतार पाना इतना सरल नहीं । हमारे देश भक्त जवानों के चिथड़ें इक्टठे करना भी मुश्क़िल हो रहा था । आतंकवाद की ठहाकों से भरी हंसी नहीं रुक रही और देश अपने जवानों की शहादत को नहीं भुला पा रहा । ऐसे में क्या अब आर–पार की जंग का वक़्त मुक़करर नहीं किया जाना चाहिए.....देश का नागरिक सोशल मीडिया और अपने–अपने तरीक़े से कह तो ऐसा ही रहा है । पर क्या पुलवामा और हर रोज़ कश्मीर को आतंक की सान पर रक्तरंजित करने का दुःस्साहस करने वाले आतंकीस्तान यानि पाकिस्तान को येन केन प्रकेरण सबक सीखाने के लिए कूटनीति और साहस का पासा चलने की ज़रुरत नहीं है ? पुलवामा में जो हुआ उससे पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध रह गया । इस हमले की सभी ने एक स्वर में निंदा की और भारत की जवाबी कार्यवाही के लिए भी समर्थन का ऐलान किया । अब गेंद भारत के पाले है कि उसे किस भाषा और तरीके से आतंकीस्तान को जवाब दें । इसकी शुरूआत हांलाकि भारत ने घर में घुसकर कद दी है।

इमरान का ईमान पाक आर्मी के पास गिरवी

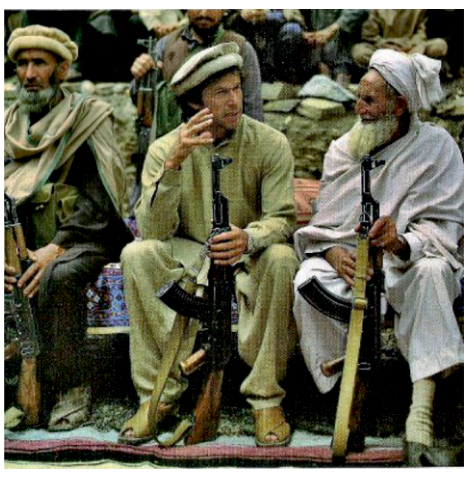

हमले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हास्यास्पद रही । पाक का मीडिया और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान बचकाना ब्यान देते हुए भारत को शांत रहने और पाकिस्तान की ऐटमी ताक़त की धौंस दिखाने से बाज नहीं आए । ईशारों ही ईशारों में भारत का डर उनकी आंखों में साफ झलकता नज़र आया । यह कहना ग़लत न होगा कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वह सब पाकिस्तान की सरकार, आर्मी और आईएसआई के ईशारों पर ही होता है । पाकिस्तान में जैश–ए–मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर में खून का नंगा तांडव मचा रखा है और इसमें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का उन्हें पूर्ण सहयोग मिलता है । कंगाली के दौर से गुज़र रहे पाकिस्तान को इमरान अपनी बचकानी ब्यानबाज़ी से और अधिक मुश्क़िल में डालते जा रहे हैं । क्योंकि इस बार भारत इस जघन्यता के लिए न तो आतंकीस्तान को माफ करेगा और न ही बदला लिए बिना चैन से बैठेगा ।

भारत की कूटनीति से पाकिस्तान में त्राहि–त्राहि

पाकिस्तान ने जो सोचा भी नहीं होगा भारत ने उसकी शुरुआत कर दी है । मोदी की कूटनीति पाकिस्तान इतनी सरलता से नहीं समझ सकता है । शुरुआती झटकों में पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो सकती है कि उसे दाने–दाने के लिए मोहताज़ होना पड़ सकता है । टमाटर 180/ से 200/ रुपये किलो. तक बिक रहे हैं । पीने का पानी भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है । नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर बांध बनाकर उसे रोकने के ब्यान से पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है । अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान से आए सैंकड़ों ट्रक सामान की ढुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन भारत थोड़ा बहुत नुकसान झेल कर पाकिस्तान को भीख मंगवाने पर उतारु हो चुका है । इस कूटनीति की तारीफ होनी चाहिए लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । इसके लिए भारत को अब आर–पार की रणनीति पर विचार ही नहीं कार्यवाही करते हुए समस्या के समाधान की ओर क़दम बढ़ाने की प्रबल आवश्यकता है । कुछ ही दिन की इस सख़्ती से इमरान खान कार्यवाही करने की बात करते हुए भारत से बातचीत की गुहार लगाने को मजबूर हो गया है ।

बाहर से ज़्यादा घर के दुश्मनों से ख़तरा

हमारे घर में घुसपैठ तभी संभव है जब घर का की कोई सदस्य बाहर वालों से मिला हो । कश्मीर पर भारत का अधिकार संवैधानिक ही नहीं बल्कि उसके कण–कण में हैं । ऐसे में कश्मीर को छोड़ना या कश्मीर में हो रहे आंतक पर चुप्पी साधने को तो सवाल ही नहीं होता । एक छोटा सा टुकड़ा जो भारत का अंग था, यदि कश्मीर में बंदूक–बंब–बारुद के डर से हथियाना चाहता है तो इसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । कश्मीर में पाकिस्तान ने वर्षों पहले जो आग लगाई थी ये उसी का परिणाम है कि आज भारत की भूमि पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं और भारत के जवानों पर पथराव भी होता है । कश्मीर में ही आडीएक्स आता है, वहीं का वाहन और फिर लाशों का अंबार भी वहीं लगाया जाता है । बाहर वालों से अधिक ख़तरा उन ज़िहादियों से है तो खाते तो भारत का हैं पर गुणगान आतंकीस्तान का करते हैं। राशन से लेकर अन्य सुविधाओं को धारा 370 की आड़ में खाने वाले देशद्राही लोग ही कश्मीर को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं जिनके पीछे आंतक के आका है जो कि बॉर्डर पार पाकिस्तान में रहते हैं। कश्मीर के अलगाववादी तथाकथित नेताओं ने कश्मीर के युवाओं को दलदल में घसीटा है। इन अलगाववादी नेताओं को पूरा समर्थन और पैसा पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों मिलता है। कश्मीर के युवाओं को नहीं मालूम कि इनको आतंक की सान पर चलाने वाले अलगाववादियों के बच्चें विदेशों में पढ़ाई और ऐशोआराम कर रहे हैं। क्या सरकार इस बात से अनभिज्ञ है कि कश्मीर में इस समस्या का आधे से ज़्यादा समाधान तो भीतर ही है। फौजियों को गलियों में मारते–पीटते रोज़ ही ऐसे विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिससे हर भारतवासी का खून खौल जाता है। हाथों में बंदूक थमा कर हमने अपनी फौज को निहथ्था बना कर रख दिया। लेकिन भारत सरकार ने पुलवामा के बहाने अब जवाब देने का पूरा अधिकार जवानों को दे कर आतंक के खात्मे के लिए एक सार्थक पहल कर दी है। पत्थरबाज युवाओं को अभी तक तो शायद माकूल जवाब नहीं मिला था लेकिन अब पत्थर का जवाब अगर गोली से मिला तो इसमें इन भटके हुए युवाओं को भी अचंभा नहीं होना चाहिए। अलगावादियों को संरक्षण मिलता रहा और आज ये नासूर बनकर भारत के सिर पर बैठ कर लगातार डंक मार रहे हैं। इनकी सुरक्षा का तामझाम ख़त्म करने के साथ ही इनकी गतिविधियों को बैन कर इन्हें देशद्रोह के लिए सख़्त कार्यवाही के दायरे में लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर के युवाओं से अपील की थी कि वे पत्थर की जगह लैपटॉप पकड़ें और कश्मीर के विकास को दिशा दें।

भारत के राजनेताओं की भूमिका भी संदिग्ध

संदिग्ध शब्द अपनेआप में बहुत कुछ ब्यां करता है । किंतु वर्तमान संदर्भ में राजनेताओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर सर्वथा उचित लगता है । बाहर से दुश्मन चोट कर रहा है और भीतर अलगाववादियों की शयमात का खेल आग में घी का काम कर रहा है । ऐसे में हमारे देश के कर्णधार अपनी भूमिका को वोट और गठबंधन व सत्ता लालच में निभा रहे हैं । यहां तक कि पुलवामा जैसे दुःखद घटनाक्रम के बाद भी देश में नेताओं की ब्यानबाजी नहीं रुकी और कई बार तो ऐसे ब्यान सामने आए जिससे एक शहीद जवान की शहादत का अपमान हुआ । 2019 के चुनावों को देखकर सत्ता और विपक्ष ने अपने–अपने तरीक़े से इस घटना को परिभाषित करने का प्रयास किया । लेकिन कश्मीर के नेताओं ने तो हदें ही पार कर दी । फारुख़ अबदुल्ला हो या महबूबा मुफ़्ती सभी ने 40 जवानों की शहादत और उसके

बाद मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के दुखद घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान से बातचीत का पुरजोर समर्थन किया । देश बदले की भावना से उबल रहा है और ये नेता बातचीत की सलाह का कटोरा लेकर घूम रहे हैं । इतना ही नहीं कश्मीरी युवाओं को भड़काने का काम भी करते रहे हैं । इनका मानना है कि ये सब होने के बाद भी पाकिस्तान को दंड नहीं देना चाहिए । यह अपराध होगा । मुझे यहां कवि की ये पंक्तियां याद आ रही है :

अन्याय सहकर चुप रहना
यह महा दुष्कर्म है
न्यायार्थ अपने बंधु को भी
दंड देना धर्म है ।।

भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि अब माफी भी मांगने पर नहीं दी जाएगी । सरकार इसका स्थाई समाधान निकाल कर ही दम लेगें हालांकि सरकार की भीतर की योजना क्या है, इसका खुलासा नहीं किया जाएगा । यानि पाकिस्तान अबके अपनी करनी का फल भुगतेगा ही । पर कैसे, कब और किन परिस्थितियों में....ये अभी उसके लिए भी रहस्य है ।

बीसीसीआई तय करे कि वो भारत के साथ है या...

इसी बीच क्रिकेट विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने का निर्णय अधिकतर खिलाड़ियों और देश के बुद्धिजीवियों का है लेकिन क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने खेलने का समर्थन किया तो गवास्कर ने भी इसका समर्थन किया । सौरव गांगुली, विरेन्द्र सहवाग, विराट कोहली सभी ने क्रिकेट न खेलने का समर्थन किया है । क्या सचिन भारतरत्न होकर भी जवानों की शहादत और पाकिस्तान की करतूतों का चाहे–अनचाहे समर्थन कर रह रहे हैं ? क्या इस प्रकार का बचकाना ब्यान उन्हें शोभा देता है?

ज़हरीले वृक्ष की पाताल तक जड़ें

कश्मीर के महाराजा हरिसिंह से विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर लिए गए तब तक कश्मीर में पाकिस्तान ने कबाईली घुसपैठियों से आधा कश्मीर कब्जा लिया गया था। एक ऐसी भयंकर भूल जो कि समय रहते हमारे कर्णधारों द्वारा सुलझाई जा सकती थी, बिगड़ती गई। हालांकि जम्मु, कश्मीर और लद्दाख बहुत भिन्नता लिए हुए हैं और इसका एक ही राज्य में विलय मात्र इसलिए कर दिया गया क्योंकि यह एक ही राजा हरिसिंह के अधीन आता था। कश्मीर में मुसलमान अधिक थे पर कश्मीरी पंडित भी कम नहीं थे। किंतु इस समस्या को गंभीरता से न लेते हुए वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में तत्कालीन समय में खून की नदियां बहा दी गई। इसी से डर कर राजा हरिसिंह ने सरकार से सहायता मांगी लेकिन सहायता शीघ्र न मिलने पर जम्मु लौट आए। अंततः कश्मीर की समस्या इस भयावक रुप से सामने आई। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जब यूएनओ में पाकिस्तान और भारत के मध्य हस्तक्षेप

की बात कर रहे थे तो उस समय हमारी फौज़ पूरे कश्मीर को अपने कब्ज़े में लेने के लिए बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। उसी समय यूएनओ की मध्यस्तता से युद्धविराम हुआ लेकिन कश्मीर का पूरा क्षेत्र अपने कब्ज़े में सेना नहीं ले पाई। 1965 में पाकिस्तान ने सैन्य बल का प्रयोग किया और भारत के करारे जवाब से मुहं की खानी पड़ी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया और कश्मीर को इस आतंक की आग में झोंक दिया।

1971 की जंग में हमारे जवानों के आगे पाकिस्तान के सेना ने घुटने टेक दिए और लगभग 1 लाख सैनिक बंदी बना लिए। लेकिन इंदिरा गांधी पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बहकावे में आ गई और बिना शर्त 1 लाख सैनिकों को छोड़ दिया । यहां पर एक ऐसा अवसर था जब हम अपनी ज़मीन से दुश्मनों को बाहर खदेड़ सकते थे वो भी अपनी शर्तों पर। क्योंकि इस समस्या के बाद 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा और कितने ही इस आग में जला दिए गए। ये जो चरणबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर में आग लगाने का काम किया है उसका व्यापक पैमाने पर असर देखा गया। पहले तो मस्ज़िदों की तादात बढ़ाना, दूसरे ग़ैरमुस्लिमों और शिया मुस्लिमों को कश्मीर से भगाना, तीसरे कश्मीर के युवाओं और आम लोगों को भारत के ख़िलाफ भड़काना और बगावत के लिए तैयार करना और आख़िर में चौथा चरण जो वर्तमान में चल रहा है, सरेआम पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे और झंडे फहराना ..... ।

देश अब समाधान चाहता है

जो हुआ उसका अफसोस विगत 72 वर्षों से देश मना रहा है। लेकिन परिणाम में हासिल हुई तो केवल आगजनी, फसाद, दंगे और खून–ख़राबा। पुलवामा ने साबित कर दिया कि संवेदनहीन हो चुके पड़ोसी को अब शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आंतकवादी देश घोषित करने के बाद इसे अलग–थलग कर हमारे जवानों की रक्त की एक–एक बूंद का हिसाब उसी भाषा में लिए जाने की प्रतीक्षा भारत का बच्चा–बच्चा कर रहा है। जिसकी शुरूआत अब हो गई है। इस आतंकवाद पर अब अंकुश लगाने की आवश्यकता भारत की प्राथमिकता होगी.....इसलिए नहीं कि देश में चुनाव है या वोट बैंक को सुरक्षित करना है बल्कि इसलिए कि देश के लोगों की सुरक्षा और जवानों की शहादत का बदला इसी तरह से श्रद्धांजलि के रुप में अर्पित किया जा सकता है।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

हिमाचल प्रदेश में 'राष्ट्र विरोधी' गतिविधियों के आरोप में दो और कश्मीरी छात्र गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दो और कश्मीरी छात्रों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता एवं पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) खुशहाल शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर निवासी पीरजादा ताबिश फैयाज और आकिब रसूल को ''राष्ट्र–विरोधी'' गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये सोलन जिले के नौनी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार बागबानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। शर्मा ने बताया कि इन छात्रों को सोलन के बेर गांव निवासी नीरज भारद्वाज की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि फैयाज ने अपने फेसबुक पेज पर राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां की थीं। शिकायत में कहा गया कि फैयाज और रसूल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और ''भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन'' कर रहे हैं। मामले की आगे जांच की जा रही है। राज्य में पुलवामा आतंकी हमले के बाद ''राष्ट्र विरोधी'' गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों की संख्या अब तीन हो गई है। तीसरा आरोपी तहसीन गुल श्रीनगर का निवासी है और वह चितकारा विश्वविद्यालय का छात्र है। उसे शनिवार को इंस्टाग्राम पर ''राष्ट्र–विरोधी'' टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

धुम्रपान छुडवाने में इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

'इनफेनिट अचीवर्स' के द्वारा किये शोध से स्पष्ट हुआ है कि धुम्रपान छुडवाने में इलेक्ट्रोनिक्स सिगरेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दावा वैक्लपिक स्मोक के लिए प्रयासरत उपभोक्ता जागरुकता समूह 'इनफेनिट अचीवर्स' का है जिसका आधार एक साल तक किये गये रेंडम ट्रायल हैं। इसमें पाया गया कि धुम्रपान छुडवाने के लिये इस्तेमाल की जाने वाले चुईन्गम की तुलना ई–सिगरेट काफी कारगर रही है। हालांकि ई–सिग्रेट का सेवन करने वालों की सफलता दर 18 फीसदी ही आंकी गई है जबकि पारम्परिक निकोटिन रिप्लेसमेंट थैरेपी की दर इससे भी बहुत कम 9.9 फीसदी रही है।

रिसर्च के दौरान नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर हैल्थ रिसर्च एंड कैंसर रिसर्च ने 886 स्मोकर्स पर ट्रायल किया। उन्होंने चार सप्ताह तक धुम्रपान छुडवाने के लिए ई–सगरेट्स और पारम्परिक निकोटिन रिप्लेसमेंट थैरेपी को अपनाया। रिसर्च में पाया गया कि ट्रायल में भाग लेने वाले 80 फीसदी प्रतिभागियों ने ई–सिगरेट के माध्यम से धुम्रपान को छोड़ दिया जबकि नौ फीसदी प्रतिभागी अंत तक निकोटिन उत्पादों के इस्तेमाल करने के बावजूद भी सिगरेट छोड नहीं पाये।

हिमाचल के 17 निजी विवि समेत 250 निजी कॉलेजों को नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में स्थित 17 निजी विश्वविद्यालयों सहित 250 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने आवश्यक जानकारी मुहैया नहीं करवाने पर यह संज्ञान लिया है। आयोग ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर चेताया है कि अब भी जानकारी नहीं दी तो संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग के सचिव एसडी नेगी ने बुधवार को सभी निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों सहित मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, डिग्री कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी, बायो साइंस, बीएड, एमएड, बीपीएड, लॉ और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर तय समय के भीतर जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

आयोग के मुताबिक कई बार निजी विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों से जानकारी मांगी गई, लेकिन आदेशों की अनदेखी हो रही है। ऐसे में आयोग को नोटिस जारी करने पड़े हैं।

राशन की कालाबाजारी
34 क्विंटल गेहूं, नौ क्विंटल चावल पकड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चुराह उपमंडल के तहत पंचायत टेपा डिपो होल्डर पर बड़े पैमाने पर राशन की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में छापा मारकर पंचायत के डिपो होल्डर के पतोगण स्टोर से पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर भारी मात्रा में सरकारी राशन की खेप बरामद की है।

हैरानी इस बात की है कि डिपो होल्डर के गोदाम में कई खाने की चीजें एक्सपायर हो चुकी थी। मगर उसने इन्हें उपभोक्ताओं को आवंटित नहीं किया। यह मामला मंगलवार को पेश आया। पुलिस ने छापे के दौरान बरामद की गई सरकारी राशन की खेप को जब्त कर लिया है।

पुलवामा हमले की प्रशंसा करने वाला छात्र न्यायिक हिरासत में भेजा गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक अदालत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक कश्मीरी छात्र को सोशल मीडिया पर एक कमेंट में पुलवामा हमले की प्रशंसा करने के आरोप में रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस ने कहा कि सोलन जिला के बद्दी में चितकारा यूनिवर्सिटी के बी.टेक के छात्र तहसीन गुल को एक कमेंट करने और आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद दार की तस्वीर अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो पर लगाने पर गिरफ्तार किया गया था।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

हिमाचल में भाजपा सांसदों के नाम पर 6000 कूड़ेदान लगाए गए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सडकों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों के नामों को दर्शाते 6,000 कूड़ेदान लगाए गए हैं। 13,000 और कूड़ेदान लगाए जाने की प्रक्रिया में हैं।

कूड़ेदानों पर प्रमुख रूप से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, शांता कुमार, राम स्वरूप शर्मा और वीरेंद्र कश्यप के नाम लिखे हुए हैं।

2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सभी चार सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्तमान में राज्य में भाजपा का शासन है।

गीले और सूखे कचरे के भंडारण के लिए जोड़े में लगाए गए इन कूड़ेदानों पर स्वच्छ भारत भी लिखा हुआ है। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के भाग के रूप में 2.66 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है।

इसी तरह, अन्य 13,000 कूड़ेदान एक अन्य केंद्रीय सरकारी उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा लगाए जाएंगे जिन पर 2.59 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

पंजाब और राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें हटाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पुलवामा हमले के बाद देशभर में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। इस बीच देश के राज्य क्रिकेट संघों ने अपने–अपने मुख्यालयों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटाने का फैसला किया है। इस लिस्ट में नया नाम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) का जुड़ गया है। एचपीसीए ने भी अपने मुख्यालय में से 13 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा ली हैं। एचपीसीए स्टेडियम के मैनेजर कर्नल एच.एस. मन्हास ने कहा, 'हमने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजली देने के लिए एचपीसीए स्टेडियम में से सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी हैं' इन तस्वीरों में शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और जावेद मियांदाद के नाम शामिल हैं। एचपीसीए स्टेडियम प्रदेश की राजधानी से 250 किलोमीटर स्थित है जो 2005 में अस्तित्व में आया था. इस स्टेडियम में उस दौरान भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश और पाकिस्तान टीम के बीच अभ्यास मैच का आयोजन किया गया था। अधिकारी ने बताया कि जो तस्वीरें थीं उनमें अधिकतर उसी अभ्यास मैच की थीं।

मुख्यमंत्री ने शहीद तिलक राज को दी अंतिम विदाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर और पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर सीआरपीएफ के जवान शहीद तिलक राज जो फरवरी की 14 तारीख को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए है, को अंतिम सम्मान देने में राज्य का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र में पैतृक गांव जंद्रो जाकर तिरंगे में लिपटे शहीद तिलक राज के ताबूत पर माल्यार्पण कर उनको अंतिम सम्मान दिया।

जम्मू–कश्मीर में पुलवामा में जैश–ए–मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे वाहन द्वारा टक्कर मारने के परिणामस्वरूप सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और पांच अन्य घायल हो गए।

मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता लायक राम, माता, पत्नी और शहीद के परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि शहीद तिलक राज ने देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुःख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ है तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने संबंधी विधेयक पारित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने संबंधी प्रावधान वाले एक विधेयक को पारित किया। हिमाचल प्रदेश आधिकारिक भाषा विधेयक, 2019 (संशोधित) को सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में बजट सत्र के दौरान पेश किया। यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया।

ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सवा 10 बजे से होंगी असेसमेंट परीक्षाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 11 मार्च से शुरू होने जा रही असेसमेंट परीक्षाएं अब सुबह सवा नौ बजे की जगह सवा दस बजे से शुरू होंगी। प्रदेश में जारी बारिश और कुल जिलों में दस बजे स्कूल खुलने के चलते शिक्षा विभाग ने यह बदलाव किया है।

समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक आशीष कोहली ने परीक्षा समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में पहली से चौथी और छठी–सातवीं कक्षा की 11 मार्च से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी।

मुख्यमंत्री ने शिमला के लिए इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के लिए एक इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'इससे शिमला के पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलेगी।' अपने बजट भाषण में जयराम ठाकुर ने अगले वित्त वर्ष से एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की थी, जो सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल, सामयिक व टिकाऊ परिवहन सुविधा प्रदान करेगी।

लोकसभा चुनाव: 40 अफसरों को एक साथ भेजने से हिमाचल सरकार का इनकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव ड्यूटी के लिए एक साथ 40 अधिकारियों को भेजने से इनकार कर दिया है। आयोग ने 25 आईएएस और 15 एचएएस अधिकारियों को मांगा है। सरकार ने कहा कि 18 आईएएस और 10 एचएएस अधिकारियों को ही भेजा जा सकेगा।

हिमाचल में अधिकारियों की भारी कमी है। 34 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं जबकि 15 इसी साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने चुनाव आयोग के एक पत्र पर जवाबी चिट्ठी में राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी पर स्थिति स्पष्ट की है।

हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने मचाया कहर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में भारी बर्फबारी के साथ–साथ बारिश ने तबाही मचा दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इसके चलते नदी–नाले उफान पर हैं। कुल्लू जिला में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ। कुल्लू शहर में मूसलाधार बारिश से पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। जिला में भूस्खलन से कुल्लू–मनाली मार्ग के साथ 50 से अधिक सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं, जिला किन्नौर में हिमस्खलन से शोंगटोंग–बारंग सड़क बंद हो गई। करछम–सांगला–छित्तकुल सड़क सांगला तक खुली रही। भूस्खलन से वांगतु से यंगपा सड़क, यंगपा से करबा और वांगतु से पवानी सड़क बंद पड़ी है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद पागलनाला में आई बाढ़ की चपेट में एक जीप आ गई। इसके बाद पानी का तेज बहाव से जीप नाले में गिर गई। चालक ने इससे पहले ही जीप से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे जीप मालिक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

हिमाचल में हिमखंड से है बड़ा खतरा इस साल 237 लोगों की गई थी जान

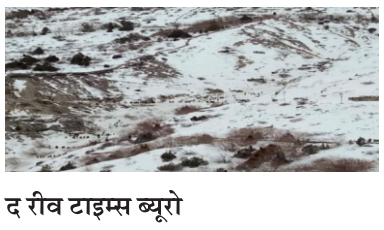

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में बीते कई सालों से हिमखंड गिर रहे हैं।

मार्च 1979 में लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने से 237 लोगों की जान गई थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक जनवरी 1975 में भूकंप के बाद हिमखंड गिरने से सड़कों को भारी नुकसान हुआ था।

मार्च 1978 में लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने से 30 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा किन्नौर में हिमखंड गिरने से करीब चार महीनों तक सड़क मार्ग बंद रहे थे। सितंबर 1995 में भी हिमखंड गिरने से बाढ़ आई थी। इससे भी सड़कों को भारी नुकसान हुआ था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला के अनुसार इस साल जनवरी महीने के दौरान प्रदेश में हिमखंड गिरने की 33 घटनाएं हो चुकी हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

यूनिसेफ ने 'बाल विवाह-2019 फैक्टशीट' नामक रिपोर्ट जारी की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (UNICEF) ने एक रिपोर्ट, 'फैक्टशीट चाइल्ड मैरिजेज़ 2019' जारी की है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है लेकिन बिहार, बंगाल और राजस्थान में यह प्रथा अब भी जारी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है। यूनिसेफ के अनुसार, अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है किंतु कुछ ज़िलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सियोल शांति पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाज़ा गया है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी आर्थिक नीतियों और विकासोन्मुखी कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इसे 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। पीएम मोदी से पहले यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिवों कोफी अन्नान और बान की-मून को भी मिल चुका है। पुरस्कार समिति ने भारत में अमीर और गरीब के बीच के सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए उनकी 'मोदीनॉमिक्स' को सराहा है। सियोल शांति पुरस्कार सांस्कृतिक फाउंडेशन के चेयरमैन क्वॉन ई-हायोक की अध्यक्षता में सियोल के जंग-यू में हुई चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था।

राजस्थान में अब अनपढ़ भी बन सकेंगे सरपंच और पार्षद, विधेयक पारित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजस्थान विधानसभा में हाल ही में पंचायतीराज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए। इन संशोधन विधेयकों के अनुसार अब पंचायतीराज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, अब अनपढ़ भी सरपंच से लेकर प्रधान प्रमुख और पार्षद से लेकर मेयर तक का चुनाव लड़ सकेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने सत्ता में आते ही न्यूनतम शिक्षा मानदंड को खत्म करने की घोषणा की थी।

हर महीने 3000 रु. पेंशन वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना लागू

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' योजना 15 फरवरी 2019 से औपचारिक रुप से लागू हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि हाल में बजट में घोषित की गई इस योजना से असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 42 करोड़ लोगों को लाभ होगा. इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह तक है और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। इस योजना के पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने चार अध्यादेशों को मंजूरी प्रदान की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 21 फरवरी 2019 को चार अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। अब यह चारों अध्यादेश क़ानून का रूप ले सकेंगे। इनमें मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) संबंधी विधेयक को दूसरी बार मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त सरकार ने कंपनी संचालन एवं अनुपालन रूपरेखा में गंभीर खाइयों को पाटने तथा देश में कारोबार सुगमता बेहतर करने के लिये कंपनी कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश जारी किया है। आधिकारिक गजट के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2019 प्रभावी हो गया है।

ग्लोबल वार्मिंग से बदल रहा है समुद्रों का रंग WEF रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका की मेसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा किये गये अध्ययन तथा विश्व आर्थिक फोरम (WEF) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व भर में समुद्रों का रंग बदल रहा है। इस अध्ययन के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण 21वीं सदी के अंत तक दुनिया के 50 प्रतिशत से अधिक समुद्रों का रंग बदल जाएगा।

एमआईटी के प्रोफेसर स्टेफनी के मुताबिक, उपोष्णकटिबंधीय (सबट्रॉपिक्स) जैसे इलाकों में पड़ने वाले समुद्रों का रंग 'गहरा नीला' और ध्रुवीय समुद्रों का रंग 'गहरा हरा' हो जाएगा। हालांकि, इन बदलावों को नग्न आंखों से देखना बहुत मुश्किल होगा। हाल ही में यह रिपोर्ट 'नेचर' पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है।

भारत ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है। हमले के मद्देनजर 15 फरवरी 2019 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तीनों सेनाध्यक्ष और सीआरपीएफ के डीजी ने भाग लिया. बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग-थलग किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार सिविल सेवा के नियम '5ए' को किया निरस्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार सिविल सर्विस (न्यायिक ब्रांच, रिक्रूटमेंट), रूल, 1995 के नियम 5ए निरस्त कर दिया. रिक्रूटमेंट, रूल, 1995 के नियम 5A के तहत पहले प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले दस गुना उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा की पीठ ने फैसले में कहा कि यह नियम स्पष्ट रूप से मनमाना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले (मजहर सुल्तान) का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि फाइनल लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को सीमित करने का यह नियम किसी मकसद को पूरा नहीं करता।

भारतीय वायुसेना को मिले 4 चिनूक हेलिकॉप्टर, जानिए क्यों है खास?

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोईंग ने 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लिए चार चिनूक सैन्य हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर की. कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सीएच 47 एफ (आई) चिनूक को चंडीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां उन्हें औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारत को कुल 15 और चिनूक हेलिकॉप्टर प्राप्त होंगे। भारत के लिए रणनीतिक नजरिए से चिनूक हेलिकॉप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके आने से एयरफोर्स की क्षमता और बढ़ जाएगी। यह हेलिकॉप्टर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हवित्जर तोपों को माल पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

अबू धाबी में हिंदी बनी न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय में इस्तेमाल के लिए अंग्रेज़ी और अरबी के अलावा हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। अबू धाबी न्याय विभाग (एडीजेडी) ने 09 फरवरी 2019 को कहा कि उसने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को शामिल करके अदालतों के समक्ष दावों के बयान के लिए भाषा के माध्यम का विस्तार कर दिया है।

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार सेवाओं के विषय पर जजों की राय अलग जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (एलजी) मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अपनी अलग-अलग राय व्यक्त की है। जस्टिस ए. के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र का अधिकार केंद्र के पास हो या दिल्ली सरकार के पास, इस मामले में अलग-अलग मत व्यक्त किया है। जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुआई वाली बेंच के पास अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर, एंटी-करप्शन ब्यूरो, सरकारी सेवा आदि पर कायम गतिरोध को दूर करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

30 दिन में NRI शादी रजिस्टर नहीं हुई तो पासपोर्ट होगा जब्त: NRI विवाह पंजीकरण विधेयक-2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों की ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्य में कहा गया कि भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण विवाह से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है। इसी के तहत भारत और भारत के बाहर होने वाले ऐसे विवाह को शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण बनाया जाना अनिवार्य किया गया है।

NABH ने अस्पतालों के लिए एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया हेतु HOPE पोर्टल शुरू किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड एनएबीएच (NABH) ने एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया को संशोधित किया है ताकि यह प्रक्रिया सरल, त्वरित, डिजिटल और इस्तेमाल में आसान हो सके। एनएबीएच ने इसके लिए एचओपीई (HOPE) नाम से एक नया पोर्टल बनाया है। इसका उद्देश्य देशभर के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे छोटी इकाइयों को उनके शुरुआती चरण में ही गुणवत्ता युक्त सेवाओं के लायक बनाना है. इसका लक्ष्य ऐसे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े ऐसे संगठनों को गति प्रदान करना भी है जो एनएबीएच प्रमाणन हासिल कर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) तथा आयुष्मान भारत से जुड़े लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और इस तरह से देश में एक गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करना चाहते हैं।

भारत में पहली बार, वायुमंडल से पानी बनाने वाला वॉटर जनरेटर हुआ लॉन्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड (बीईएल) ने एक नए उत्पाद एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर (एडब्ल्यूजी) का 21 फरवरी 2019 को एयरो इंडिया 2019 में अनावरण किया है। यह उत्पाद दुनिया में पेयजल की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए एक नवाचार समाधान उपलब्ध कराता है। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने एडब्ल्यूजी का बीईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम वी गौतम और कंपनी के निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। बीईएल का यह एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर (एडब्ल्यूजी) वायुमंडल में मौजूद नमी से सीधे ही पानी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है. वह दिन दूर नहीं जब पेयजल इस ग्रह पर सबसे कीमती चीज बन जाएगा। वर्तमान में भूजल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा की अपनी यात्रा के क्रम में 09 फरवरी 2019 को ईटानगर पहुंचे। उन्होंने ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और सेला टनल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने डीडी अरुण प्रभा चैनल का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के आईजी पार्क से कई अन्य विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने वहां लॉइन लूम संचालन का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने होलांगी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी तथा तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

'ग्रीन बुक' बेस्ट फिल्म, 'लेडी गागा' बेस्ट सिंगर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के कैलिफॉर्निया स्थित डॉल्बी थिएटर में सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscar Awards 2019) की घोषणा की गई। इस पुरस्कार समारोह में भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी 'पीरियड' एंड ऑफ सेंटेंस' को भी बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवॉर्ड मिला है।

बेस्ट फिल्म कैटेगरी में आठ फिल्म को आखिरी सूची में रखा गया था। इनमें ब्लैक पैंथर, ब्लैक लेंसमैन, बोहिमिया रापसोडी, द फेवरेट, ग्रीन बुक, रोमा, ए स्टार इज़ बोर्न, वाइस का नाम शामिल था। सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 'ग्रीन बुक' ने बेस्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया।

GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया हैं।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से पीएम-किसान योजना लॉन्च की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का शुभारंभ किया गया। लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर एक करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री -किसान योजना के तहत चुने हुए किसानों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अबू धाबी की अदालतों में हिंदी के तीसरी भाषा बनने का महत्व

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिंदी अब कहां नहीं है। हिंदी का राज अब दूर–दूर तक है। लगभग दुनिया के हर हिस्से में अब आपको कोई न कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा। भारत माता के माथे की बिंदी हिंदी अब विदेशों में भी सम्मानजनक दर्जा हासिल कर भारत का मान बढ़ा रही है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हिंदी को अदालत की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना दुनिया भर में हिंदी को मिल रहे सम्मान की एक और नई मिसाल बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने देश में रह रहे हरेक तबके और समुदाय तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

भारत की चौतरफा घेराबंदी के बाद अब दुनिया को सफाई दे रहा पाकिस्तान

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पुलवामा पर भारत की चौतरफा कूटनीतिक घेराबंदी के बाद पाकिस्तान अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा है, सफाई देते फिर रहा है। 2002 से प्रतिबंधित जैश के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करने का दावा भी कर रहा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है। जैश सरगना मसूद अजहर न सिर्फ पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह लिए है, बल्कि वह खुलेआम घूमता है, रैलियां करता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है।

भारत ने नई दिल्ली में पी 5 के सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 25 देशों के राजदूतों को पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के ठोस सुबूत दिए थे। भारत ने बताया था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बना लिया है।

भारत ने पाक के कार्यवाहक उच्चायुक्त को किया तलब, पायलट को फौरन लौटाने की मांग की

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारत ने पाकिस्तान को कहा कि वह भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को फौरन और सुरक्षित लौटा दे। दरअसल, दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच हुई एक झड़प के बाद पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया है। साथ ही, एक घायल रक्षा कर्मी को पड़ोसी देश द्वारा ''अशोभनीय तरीके से दिखाए जाने पर'' भी भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। सैन्य चौकियों को निशाना बनाए जाने सहित पाकिस्तान द्वार बगैर उकसावे के आक्रमण करने पर सख्त ऐतराज जताने के लिए पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। मंत्रालय ने कहा कि दूत से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए दृढ और निर्णायक कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय रक्षाकर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच भीषण झड़प के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया।

दुनिया भर के विरोध के बावजूद आतंकी अजहर मसूद पर क्यों अड़ा है चीन

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सभी की निगाह चीन पर लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ही वह देश है जो हमेशा से मसूद अजहर के मामले में अड़ंगा लगाता रहा है। मसूद अजहर का यहां जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। इस आतंकी संगठन का हैडक्वार्टर भी पाकिस्तान के रावलपिंडी में है।

चीन के विदेश मंत्री जेंग शुआंग ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम इस हमले में शहीद हुए सभी जवानों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन इस तरह के किसी भी हमले की निंदा करता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देश क्षेत्र की शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग करेंगे। जब उनसे आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में डालने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल किया गया है।

भारत ने वापस लिया MFN का दर्जा पाकिस्तान बोला हमें खबर नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का बेतुका बयान सामने आया है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने रविवार को कहा कि, भारत ने पाकिस्तान को सूचित नहीं किया है कि वह मोस्ट फेवर्ड नेशन (डथ्छ) का दर्जा वापस ले रहा है। अब्दुल रजाक के हवाले से जियो न्यूज ने बताया कि अभी तक नई दिल्ली की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी इस संबंध में नहीं दी गई है। बता दें कि गुरुवार को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (सर्वाधिक तरजीही देश) का दर्जा छीन लिया था और आयात सामानों पर 200 फीसद कस्टम ड्यूटी लगा दी थी।

सियोल में बोले पीएम मोदी, भारत पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारत संभावनाओं की भूमि के तौर पर उभरा है। जब हम साथ काम करते हैं तो सपने साकार करने की दिशा में काम करते हैं, हम समान विचार वाले सहयोगियों की तलाश करते हैं। हम दक्षिण कोरिया को वास्तव में स्वाभाविक भागीदार के रूप में देखते हैं। कोरिया की भूमि पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने ये बात कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के साथ भारत के सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने और व्यापार एवं निवेश समेत विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे हैं।

मुशर्रफ ने माना पुलवामा हमले में जैश का हाथ, पाकिस्तान को बताया निर्दोष

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद (जेईएम) का जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हाथ है। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। बुधवार को एक निजी न्यूज चौनल को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने हमले पर दुख व्यक्त किया और इसकी निंदा की। हालांकि उन्होंने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रुप से भारत को चेतावनी भी दी कि कश्मीर पर अपना अधिकार न जताए भारत।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा स्वराज कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुल्गारिया में अपने समकक्ष कैटरीना जहारिएवा से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। सुषमा की अपनी बल्गारियाई समकक्ष कैटरीना के साथ कई नए क्षेत्रों पर भी बात हुई। इनमें फार्मास्युटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान–प्रदान शामिल है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह किसी भारतीय विदेश मंत्री की बुल्गारिया की पहली यात्रा रही। विदेश मंत्री यहां दो दिन आधिकारिक यात्रा पर थी।

पुलवामा पर अलग–थलग पड़ा पाक, जापान से मदद मांगने गया पाक को मिला ये जवाब

द रीव टाइम्स ब्यूरो : पुलवामा आतंकी हमले के बाद गुरुवार को जापान ने इसकी कड़ी निंदा की है। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चहिए। जापानी विदेश मंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। इसके साथ ही जापान ने पाकिस्तान से संयम बरतने की भी नसीहत दी है। जापानी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब पुलवामा हमले के बाद पैदा हुए हालात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने जापान की अपनी यात्रा टाल दी थी। उन्होंने जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो को फोन कर बताया कि मौजूदा हालात के चलते वह देश छोड़कर आने में असमर्थ हैं।

साउथ कोरिया: पीएम मोदी ने किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, किया याद

द रीव टाइम्स ब्यूरो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने गांधी के संदेशों के जरिए आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात कही। मोदी ने कहा कि बापू के विचार और आइडियाज की मदद से हम लोग आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे दो बड़ी चुनौतियों से पार पा सकते हैं।

नेप्च्यून का नया चांद मिला, हो सकता है एलियंस का संभावित ठिकाना

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

ब्रह्मांड में नित नई खोज में लगे रहने वाले खगोल–विज्ञानियों को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह नेप्च्यून के पास एक नया चांद खोज निकाला है। इसे एलयिंस का संभावित ठिकाना भी माना जा रहा है। खगोल–विज्ञानियों ने इस नए चांद का नाम हिप्पोकैंप रखा है। बता दें कि हिप्पोकैंप जो है वह नेप्च्यून का इलकौता चांद नहीं है। बल्कि उसके पास पहले से अपने 13 और चांद मौजूद हैं।

कैसा है नया चांद

नेप्च्यून के नए चांद का साइज करीब 18 मील है। यह भारत के इकलौते चांद से करीब 100 गुना छोटा है। खगोल–विज्ञानियों को लगता है कि हिप्पोकैंप नेप्च्यून के ही दूसरे चांद प्रोटियस का टूटा हुआ हिस्सा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि कोई धूमकेतु प्रोटियस से जाकर टकराया होगा जिससे हिप्पोकैंप का निर्माण हुआ। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हिप्पोकैंप नाम का जिक्र है। इसका मतलब एक विशालकाय समुद्री जीव होता है। इसका शरीर घोड़े का और पीछे मछली की पूंछ लगी होती है।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग से 69 लोगों की मौत, राहत व बचाव कार्य जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के घनी आबादी वाले इलाकों में रात को केमिकल व प्लास्टिक वेयरहाउस में आग लगने से कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। हताहतों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फायर अफसर का कहना है कि हताहतों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है, क्योंकि आग में सैकड़ों लोग इमारतों के अंदर फंसे हैं।

यह आग राजधानी ढाका के चौकबाजार वाले संकरे इलाके में लगी। इस क्षेत्र में रिहायशी और कमर्शियल दुकानें और रेस्टोरेंट हैं। बांग्लादेश के फायर सर्विस के प्रमुख अली अहमद ने बताया कि अभी तक हमने 69 शव बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि शवों की संख्या बढ़ सकती है। शवों की खोज के साथ राहत और बचाव कार्य जारी रहे।

किम कुमारी को मिला मिस इंडिया–यूएसए का ताज

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

न्यूजर्सी की किम कुमारी ने मिस इंडिया–यूएसए 2019 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में विधि दवे को श्रीमती इंडिया–यूएसए 2019 का खिताब मिला और ईशा चंद्र कोडे को मिस टीन इंडिया–यूएसए 2019 का ताज मिला।

हालांकि न्यूजर्सी के फोर्ड्स सिटी में आयोजित इस भव्य सौंदर्य स्पर्धा में मिस इंडिया–यूएसए की द्वितीय विजेता न्यूयॉर्क की रेणुका जोसफ और तृतीय विजेता फ्लोरिडा की आंचल शाह रहीं। इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा आयोजित और जानी–मानी भारतीय अमेरिकी नीलम और धर्मात्मा सरन की अध्यक्षता में हर साल होने वाली 'मिस इंडिया–यूएसए' भारत के बाहर आयोजित होने वाली भारतीय सौंदर्य स्पर्धा है।

पड़ोसियों के लिए खतरा बना पाक: ईरान में 27 रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की हत्या में भी निकला हाथ

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पाकिस्तान भारत ही नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों में आतंकी भेजकर वहां अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के खास प्रशिक्षित बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पर इसी हफ्ते हुए हमले की जांच में पता चला है कि आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान से आया था और उसे वहां की खुफिया एजेंसी ने प्रशिक्षित किया था।

हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 27 कमांडो मारे गए थे। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को इस हमले के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरानी सत्ता में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का खास रुतबा है। रिवोल्यूशनरी गार्डस के प्रमुख मेजर जनरल मुहम्मद अली जाफरी ने आत्मघाती हमले के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समर्थित सुन्नी आतंकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा बल इस तरह के संगठनों को क्यों पनाह देते हैं। सरकारी टेलीविजन पर जाफरी ने कहा, पाकिस्तान को निसंदेह इस हरकत की बड़ी कीमत चुकानी होगी।

पाकिस्तान हमले की 'भारी कीमत' चुकाएगा: ईरान

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी।

अब ईरान ने भी पड़ोसी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाने की धमकी है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान में पनाह लिए चरमपंथियों ने इस हफ्ते उसके रिवॉल्युशनरी गार्ड्स के 27 जवानों पर आत्मघाती हमला कर उनकी जान ले ली थी।

ईरान के रिवॉल्युशनरी गार्ड्स प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने इस हमले में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सुन्नी समूहों को मदद करने का आरोप लगाया है।

मोरक्को में सुषमा स्वराज के सामने मोरक्कन सिंगर ने गाया 'वैष्णव जन तो तेने कहिए'

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुल्गारिया से मोरक्को की राजधानी रबात पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान सुषमा स्वराज ने पुलवामा को लेकर अपना दुख ज़ाहिर किया। भेंट वार्ता के दौरान सुषमा स्वराज के सामने मोरक्कन सिंगर नसर मेगरी ने महात्मा गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रस्तुत किया।

नेपाल भूकंप: नागरिकों को बचाने के लिए स्पेन ने भारत को किया सम्मानित

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

नेपाल में 2015 में आए भूकंप में पीड़ितों की मदद के लिए भारत की तत्परता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। अब स्पेन ने अपने 71 नागरिकों को सुरक्षित निकालने में भारत के सहयोग को मान्यता दी है। इसी क्रम में स्पेन सरकार ने भारत को प्रतिष्ठित 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट' से नवाजा। स्पेन दौरे पर गईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत की तरफ से इसे स्वीकार किया।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करेंट अफेयर्स

- नासा के मुताबिक, मंगल ग्रह पर उसका ऑपरच्यूनिटी रोवर मिशन जितने वर्ष बाद निष्क्रिय हो गया है–15 वर्ष
- नासा के एक ताजा अध्ययन में आम अवधारणा के विपरीत यह पाया गया है कि भारत और वह देश जो पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं– चीन
- प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में जिस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया– इजराइल
- केंद्र सरकार ने रेलवे सेवा के जिस सेवानिवृत्त अधिकारी को दोबारा सार्वजनिक विमानन कंपनी एअर इंडिया का चेयरमैन व एमडी (सीएमडी) नियुक्त किया है– अश्वनी लोहानी
- एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय को इतने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है–30 दिन
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जिस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है – फ़िनलैंड
- वह स्थान जहां हाल ही में दक्षिण–पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है–चेन्नई
- सुप्रीम कोर्ट के वह जस्टिस जिन्होंने आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार एलजी को दिए जाने की राय व्यक्त की है –जस्टिस ए. के. सीकरी
- वह राज्य जहां गुर्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है–राजस्थान
- हॉन्ग–कॉन्ग यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक, रात में जितने घंटे से कम नींद लेने के कारण डीएनए को नुकसान होने के साथ–साथ शरीर में डीएनए रिपेयर की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है– सात घंटे
- ग्लोबल इकोलॉजी ऐंड बायोजियोग्राफी में छपे अध्ययन के मुताबिक, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत कशेरुकी जीवों (स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप) की मौत के लिए इंसान सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं–28 प्रतिशत
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के मुताबिक, वह मंत्रालय जिसने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान संसद की पूर्वानुमति के बिना 1,156.80 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं – वित्त मंत्रालय
- वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण जिस वर्ष तक बंगाल टाइगर का आखिरी तटीय गढ़ 'सुंदरवन' नष्ट हो सकता है– वर्ष 2070
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत जितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है– सात
- वह स्थान जहां वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में हितधारकों के लिये आउटरीच' कार्यक्रम का आयोजन किया गया–नई दिल्ली
- वह स्थान जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज तथा 510 बिस्तर वाला अस्पताल देश को समर्पित किया –फरीदाबाद
- वह संस्थान जिसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन–2019 का आयोजन किया जा रहा है–नई दिल्ली
- इन्हें हाल ही में अफरीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है – अब्देल फतह अल–सीसी
- वह विधानसभा जिसने हाल ही में संशोधन विधेयकों द्वारा पंचायतीराज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी है–राजस्थान
- वह राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वच्छ शक्ति–2019 कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार प्रदान किये– हरियाणा
- वह सरकारी इमारत जहां पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया गया – संसद का केन्द्रीय कक्ष
- वह देश जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 20,000 पाकिस्तानी छात्रों को स्कॉलरशिप दिये जाने की घोषणा की गई है–चीन
- वह राज्य जिसने आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है–तमिलनाडु
- वह स्थान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षयपात्र फाउंडेशन के तहत 300 करोड़वीं थाली में खाना परोसा–वृंदावन
- मेसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में ध्रुवीय समुद्रों का रंग होगा – गहरा हरा
- वह स्थान जहां मिथिलाक्षर के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है –दरभंगा
- बजट 2019 में घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को सालभर में इतनी राशि का आय समर्थन दिया जायेगा –6000 रुपये
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी ने अरबी और अंग्रेजी के बाद जिस भाषा को न्यायालय में इस्तेमाल के लिए तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है– हिंदी
- न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 10 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में तीसरा मैच खेलने के साथ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जितने टी–20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं–300 टी–20
- जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के सहायक कोच नियुक्त किया गया हैं– रिकी पॉन्टिंग
- जिस देश की यूनिवर्सिटी एमआईटी के अध्ययन के मुताबिक, ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण 21वीं सदी के अंत तक दुनिया के 50 प्रतिशत से अधिक समुद्रों का रंग बदल जाएगा– अमेरिका
- रियो ओलंपिक्स रजत विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीनी स्पोर्ट्स ब्रैंड ली निंग के साथ जितने साल के लिए 50 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है–4 साल
- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कितने दिन के अंदर देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का आदेश दिया है–90 दिन
- भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका से इन हेलिकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है–चिनूक हेलिकॉप्टर
- जम्मू–कश्मीर प्रशासन द्वारा लद्दाख को पृथक मंडल घोषित करने के बाद राज्य में प्रशासनिक इकाईयों की संख्या होगी – 3
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आरंभ की गई सुरंग का क्या नाम है – से–ला सुरंग
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास की गई बरौनी–गुवाहाटी गैस पाइप लाइन की लम्बाई है – 729 किलोमीटर
- कपड़ा मंत्रालय द्वारा रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जिस मोबाइल एप्लिकेशन को लॉन्च किया है उसका नाम है – ई–कोकून
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 10 फरवरी 2019 को किस राज्य के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया– हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर जितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है–25,000 रुपये प्रति माह
- हाल ही में जिस सरकार ने संकरी जगहों के लिए 16 बाइक ऐम्बुलेंस लॉन्च की हैं– दिल्ली सरकार
- आरबीआई ने छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी मिलने वाले कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर जितने लाख रुपये कर दी है–1.6 लाख रुपये
- संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जिस दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की आदमकद प्रतिमा 12 फरवरी को लगाई जाएगी– अटल बिहारी वाजपेयी
- अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में भारत आठ स्थानों की छलांग के साथ जितने पायदान पर पहुंच गया–36वें
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन्हें हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है – डेविड मल्पस
- वह स्थान जहां परमाणु टेक–2019 सम्मेलन आयोजित किया गया – नई दिल्ली
- वर्ष 2019–20 का बजट पेश करते हुए शहरों में कान्हा गोशाला के लिए इतने करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई –200 करोड़ रुपये
- वह राज्य जिसके द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है –असम
- केंद्र सरकार द्वारा पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक है – अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक–2018
- सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसार पायरेसी और कॉपीराइट मामलों का उल्लंघन करने पर इतने साल की सज़ा हो सकती है–तीन साल
- वह स्थान जहां हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया है–नई दिल्ली
- वह राज्य जिसने हाल ही में कालिया छात्रवृत्ति योजना–2019 शुरू की है–ओडिशा
- वह राजनेता जिसने हाल ही में बाढ़ में लोगों को बचाने वाले केरल के मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है –शशि थरूर

हिमाचल सामान्य ज्ञान

प्रदेश में कुल कितने मछली पालन केंद्र हैं–8

हाल ही में चंबा के भांदल ट्राउट सेंटर का सरकार ने अधिग्रहण किया है–प्रदेश में कुल 20 टन उत्पादन किया जा रहा है

किस जिले में देवी देवताओं के माध्यम से बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का संदेश देने का अभियान शुरू किया गया है–मंडी में

दालंग जहां हिमखंड गिरने से सेना का कैंप क्षतिग्रस्त हो गया, किस जिले में है– लाहुल स्पीति

कोची में विंग्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है– नेवी में सेवाएं दे रही सब लेफ्टीनेंट अपूर्वा शर्मा को, वह कांगड़ा के पालमपुर में अंदरेटा की रहने वाली है

छेशु मेला कहां और किससे संबंधित है– यह मेला रिवाल्सर में मनाया जाता है और पदमसंभव के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित किया जाता है।

हिमाचल के किस जिले में नाग लोक की मूर्तियां स्थापित की जा रही है–जिला सोलन में

हिमाचल प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है–देवेश कुमार को

लोसर उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है–किन्नौर में, तिब्बती समुदाय की ओर से नववर्ष के आगमन के मौके पर

मौजूदा वित्त वर्ष की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3142 करोड़ 65 लाख रूपये की जरूरतों को पूरा करने की मंजूरी मिली है

प्रदेश में कहां कहां ट्रामा सेंटर खोले जाने है–ऊना, नालागढ़ और कोटखाई

किस महिला किसान पर दूरदर्शन द्वारा विशेष डाक्यूमेंटरी तैयार की गई–कल्पना शर्मा, सुंदरनगर

हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल द्वारा पहला शैक्षणिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है– मोगीनंद स्कूल सिरमौर , स्टेशन का नाम है हैलो मोगीनंद

गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया जा गया है– बद्दी के अशोक कुमार को

हिमाचल में कौन सी भाषा को दूसरी अधिकारिक भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है – संस्कृत

हाल ही में ऑल इंडिया साई जूनियर कबड्डी का प्रशिक्षण ले रही हैं–मनाली के कनियाल गांव की महिमा ठाकुर

11 से 17 फरवरी

ऊना के किय गांव में क्रिमिका फूड पार्क बन रहा है– सिंगा गांव में

कुल्लू में होली उत्सव कब शुरू होता है– बसंत पंचमी के दिन से, यह उत्सव 40 दिन तक चलता है

सिरमौरी चिता के नाम से किसे जाना जाता है– सुनील शर्मा। सुनील ब्राजील में अल्ट्रा मैराथन फॉर 135 माइल्स दौड़ को क्वालीफाई करने वाले सुनील शर्मा देश के तीसरे धावक बन गए हैं। वह सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र के निवासी है।

समुद्र के रास्ते चक्कर लगाने वाली भारतीय नौसेना की टीम तारीणी का लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल है। इसमें कुल्लू के माहौल से संबंध रखने वाली प्रतिभा जंबवाल भी शामिल थी। यह यात्रा 10 सितंबर 2017 को देश में ही निर्मित

बजट फैक्ट

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 44,387.73 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। जबकि पिछला बजट 41.440 करोड़ रूप्ये का था। इस तरह ये यह 7 फीसदी यानी 2948 करोड़ रूपये बढ़ा। यह वृद्धि 7 फीसदी यानी 2948 करोड़ रूपये बढ़ा

इस तरह होगा 100 रूप्ये का आवंटन

वेतन– 27.85 रूप्ये

पेंशन– 15 रूपये

ब्याज अदायगी 10.25 रूपये

ऋण अदायगी–7.35 रूप्ये

विकास कार्य – 39.56 रूपये

2018–2019 योजना का आकार कितना है– 7100 करोड़ रूपये

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हिमाचल प्रदेश की विकास दर क्या रहने का अनुमान है– 7.1

प्रदेश के सकल घरेलु उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है–11.2 प्रतिशत

अंतरिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 1,51,835 करोड़ रूपये

14 दिसंबर 2018 को नीति आयोग ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में हिमाचल को कौन सा स्थान मिला है' प्रथम

नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकताओं के लिए जारी होने वाली धनराशि में कितनी वृद्धि की गई है– 90 करोड़ से बढ़ाकर 105 करोड़

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को 1.25 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ कर दिया गया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

एक फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में किसानों और निचले तबके के लोगों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है। इसमें किसानों के लिए निधि योजना शुरू की गई तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी पहली बार पेंशन योजना की शुरूआत की गई। हालांकि इस योजना का लाभ श्रमिको को उनके ही द्वारा दिए गए अंशदान से मिलेगा लेकिन इसमें सरकार भी अपना योगदान देगी और असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भविष्य में वित्तिय असुरक्षा की भावना से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे कि इस योजना का लाभ लेने के पात्र लोग कैसे योजना से जुड़कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं–

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत 15 फरवरी से हो चुकी है यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जिसकी ब्याज दर को संगठित क्षेत्र के पेंशन फंड के ब्याज 8.55 फीसदी के करीब रखा जाएगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने अभी तक ब्याज दर की घोषणा नहीं की है। यह योजना लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) द्वारा चलाई जाएगी। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इस स्कीम की घोषणा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

योजना से जुड़ी खास बातें

ये हो सकते हैं शामिल

अधिसूचना के मुताबिक, यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू होगी। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड–डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं।

कितना करना होगा अंशदान

योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी. इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जाएगा। योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा. योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा।

आधार जरुरी

मेगा पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रुपये महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा

वर्कर की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

किश्त न देने पर क्या करना होगा

अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।

मौत होने पर क्या होगा

योजना में यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई कामगार नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी। वह आगे नियमित रूप से योजना में अंशदान कर सकती है। लाभार्थी की पत्नी अथवा पति अंशदाता की मृत्यु होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते हैं तो वह किए गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते हैं और योजना से बाहर हो सकते हैं।

विकलांग होने पर क्या होगा

योजना के लाभार्थी के स्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में भी उसके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा बाहर हो सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, सिर–पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन' योजना 15 फरवरी 2019 से औपचारिक

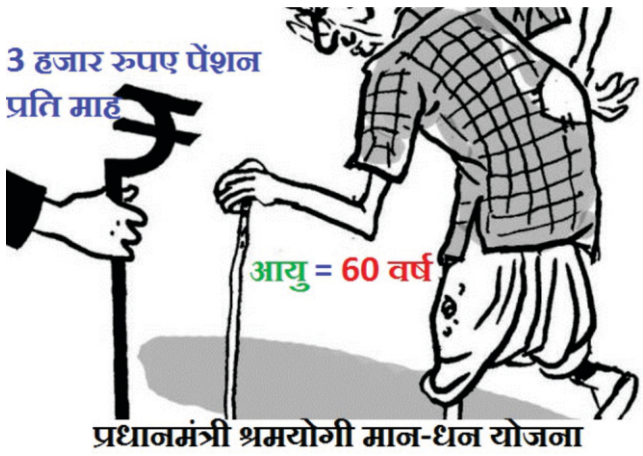

रुप से लागू हो गई है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि हाल में बजट में घोषित की गई इस योजना से असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 42 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह तक है और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। इस योजना के पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

पीएम–एसवाईएम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

न्यूनतम निश्चित पेंशनः पीएम–एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा।

परिवार पेंशनः यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से "ऑटो डेबिट" सुविधा के माध्यम से किया जाएगा. पीएम–एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी.

केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदानः पीएम–एसवाईएम 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है।

पात्र अभिदाता नजदीकी सीएससी जाकर आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके पीएम–एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं।

बाद में अभिदाता को पीएम–एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता/जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा चलाया जाएगा।

असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी

रसीद दी जाएगी।

एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों, ईएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना, उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।

योजना से बाहर निकलना और वापसी

असंगठित मजदूरों के रोजगार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकालने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं। योजना से बाहर निकलने के प्रावधान निम्नलिखित हैं–

यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा।

यदि अभिदाता 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो, के साथ दिया जाएगा। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है।

असंगठित क्षेत्र–एक परिचय

अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र से जुड़े रोजगारों का एक विशाल बहुमत भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08 के अनुसार भारत में कार्यरत 93 प्रतिशत स्वरोजगारी और रोजगाररत कर्मचारियों की संख्या असंगठित क्षेत्र में जुड़ी थी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को असंगठित श्रम बल के अनुसार– व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से व्यथित श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के मामले में चार समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

व्यवसाय के संदर्भ में

छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, हिस्सा साझा करने वाले, मछुआरे, पशुपालक, बीड़ी रोलिंग करनेवाले, ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करनेवाले, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, चमड़े के कारीगर, बुनकर, कारीगर, नमक मजदूर, तेल मिलों आदि में कार्यरत श्रमिकों इस श्रेणी के अंतर्गत माना गया है।

रोजगार की प्रगति के संदर्भ में

संलग्न खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनुबंधी और दैनिक मजदूर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

विशेष व्यथित श्रेणियों के संदर्भ में

ताड़ी बनाने वाले, सफाईकर्मी, सिर पर भार ढोने वाले, पशु चालित वाहन वाले श्रमिक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

सेवा श्रेणियों के संदर्भ में

घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, न्यूज पेपर विक्रेता आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

हिमाचल में बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई महत्पूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने और बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी ही एक योजना है–'बेटी है अनमोल' । इस योजना को केंद्र सरकार की ओर से शुरु की गई योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से भी प्रेरित माना जाता है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिमाचल सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं।

बेटी है अनमोल

योजना क्या है–

बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक की छात्राओं को छात्रवृति देने का प्रावधान तो है ही, साथ ही बेटी के जन्म पर एफडी कराने का भी प्रावधान है।

यहां समझे वित्तीय सहायता का लाभ

बीपीएल परिवार की सूची में नामित परिवार मे जब कोई बेटी जन्म लेती है तो जन्म का पंजीकरण होने के साथ ही वह योजना का लाभ लेने की पात्र हो जाती है। तय प्रावधानों के मुताबिक जन्म पंजीकरण होने पर बेटी के खाते में 10 हजार की एफडी के तौर पर सरकार की ओर से महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से बेटी के नाम से खाते में जमा किये जाते है। यह लाभ एक परिवार में जन्म लेने वाली अधिकतम दो बेटियों को मिलता है।

स्कूल में दाखिले पर छात्रवृत्ति

जन्म के समय खाते में 10 हजार की एफडी कराने के अलावा जैसे ही बेटी का स्कूल में दाखिला होता है उस समय भी सरकार की ओर से बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हिमाचल सरकार पहली कक्षा से 12 वीं कक्षा तक की लड़कियों को 300–1200 रुपये छात्रवृत्ति देती है। इसके अलावा कॉलेज जाने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप में

वित्तीय मदद देकर हिमाचल सरकार प्रदेश में महिलाओं में उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहती है।

स्नातक पर मिलेगी छात्रवृत्ति

सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से स्नातक स्तर पर समकक्ष पाठ्यक्रमों और अन्य कोर्स में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को 5,000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देती है।

कैसे करें आवेदन

इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग और मेडिकल–लॉ आदि की पढ़ाई कर रही बेटियां इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पा सकती हैं।

क्या चाहिए दस्तावेज

बेटी हैं अनमोल योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात –आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र साथ लगाने होंगे।

क्या है बेटी है अनमोल योजना की पात्रता?

बेटी है अनमोल योजना के तहत 5 जुलाई 2010 के बाद पैदा हुई स लड़कियों को 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई पर मिलने वाले लाभ मिल सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार की बेटी है अनमोल योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें––––

http://edistrict.hp.gov.in./pages/staticSite/serviceList.xhtml

इस लिंक पर आपको बेटी है अनमोल योजना का लिंक दिखाई देगा। उसके दायीं तरफ आप अप्लाय बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलेगा। इसे सबमिट करने के बाद आपका आवेदन सरकार के पास पहुंच जायेगा। अगर आप बेटी है अनमोल योजना के तहत आवेदन पत्र भरकर और जरूरी दस्तावेज लगाकर अप्लाय करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

https://himachalforms.nic.in/pdfs/Women-Child-Dev/BetiHaiAnmolYojna.pdf

इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके समाने बेटी है अनमोल योजना आवेदन फार्म खुलेगा। इस फार्म

इसे डाउनलोड करने के बाद भरकर आप सभी दस्तावेज लगायें और नजदीकी लोकमित्र केंद्र, आंगनबाड़ी या सीडीपीओ के दफ्तर में जमा करा सकते हैं।

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र

बाल विकास परियोजना अधिकारी
बाल विकास योजना
जिला.....हि.प्र.

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि मेरे परिवार में दिनांक ..... को पहली/दूसरी बालिका का जन्म हुआ है। मैं हि.प्र. का स्थाई निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम श्रीमति..... है। मेरा परिवार गरीबी रेखा में चिन्हित परिवारों की सूचि मे है तथा इसका BPL.NO..... है। अत: निवेदन है कि मेरी बेटी को हि.प्र. सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभ प्रदान करें।

1 बेटी के पिता/मात का नाम
2 बेटी का नाम (प्रार्थी के हस्ताक्षर)
3 बेटी के जन्म की तिथि
4 परिवार मे बेटी की संख्या/कम (पहला/दूसरा)

1. प्रमाणित किया किया जाता है की उपरोक्त आवेदक द्वारा दर्शाए गए तथ्य सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति.....BPL के अंतर्गत चयनित है तथा सूचि में क्र. स. ..... पर प्रदर्शित है।

ख़्वाब ऊँचे देखने दें आज बेटी को
दीजियेगा पंख औ' परवाज़ बेटी को

करने पूरी हर तमन्ना हौसला दीजे
दीजिये नव ऊर्जा, अंदाज़ बेटी को

चूल्हे-चौके से न हो अब वास्ता फ़क़त
सौंनियेगा राज-काज, ताज बेटी को

नाज़ करेगी सुखद अंजाम पर दुनिया
करने तो दीजे इक दफ़ा आग़ाज़ बेटी को

शपथ लीजिये कि ना लाचार समझेगा
देगा बराबरी का हक़ समाज बेटी को

अनिल गोयल

HP/129/SML/2019-2021

मनुष्यों की तरह सीधे चलते थे निएंडरथल मानव

द रीव टाइम्स ब्यूरो : इंसानों के विकास क्रम के विषय में वैज्ञानिकों के मत भिन्न–भिन्न हैं । कुछ के साक्ष्य प्राप्त हैं, जबकि कई के बारे में अध्ययन जारी है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने निएंडरथल मानवों के बारे में अहम जानकारी का पता लगाया है । वैज्ञानिकों का कहना है कि निएंडरथल मानवों को अक्सर खराब आसन के रूप में दिखाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वे आधुनिक मानवों की तरह सीधे चलते थे । वैज्ञानिकों के मुताबिक, ये गुफा मानव हमारे अब तक के अनुमानों की तुलना में आधुनिक मानवों से अधिक समानता रखते थे ।

स्विट्जरलैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है । शोधकर्ताओं ने फ्रांस में पाए गए निएंडरथल मानवों के कंकालों की रीढ़ और आकृति का अध्ययन किया । इसके आधार पर उनका कहना है जिन मानवों को हम झुक कर चलने वाला मानते थे, वे वास्तव में हमारी तरह सीधे खड़े होते थे और सीधा चलते थे

कौन थे ये प्राचीन मानव

निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुईं थीं, जिसके आधार पर इनका नाम निएंडरथल मानव रखा गया था । माना जाता है कि इनका कद अन्य मानवजातियों की अपेक्षा छोटा था । अभी तक के अध्ययनों से प्राप्त जानकारियों के मुताबिक, इनका कद 4.5 से 5.5 फिट तक था। यह पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में रहते थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह लगभग 1.60 लाख वर्ष पूर्व धरती पर रहते थे। इनका श्रेणी विभाजन मनुष्य की ही एक उपजाति के रूप में किया जाता है । 2007 में किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि इनके बालों का रंग लाल तथा त्वचा पीली थी ।

एक बार फिर राष्ट्रवाद के साये में हो रहा है आम चुनाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दो दशक बाद जल्द होने वाला आम चुनाव राष्ट्रवाद के साये में ही होगा, ये तो अब तय लग रहा है। पुलवामा हमला मामले में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत भारतीय वायु सेना के सर्जिकल 2 को अंजाम देने के बाद भाजपा गदगद है। पार्टी को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद बही राष्ट्रवादी बयार बीते आम चुनाव की तरह पीएम मोदी के पक्ष में लहर पैदा करेगी। गौरतलब है कि तब एक वोट से सरकार गिरने के बाद कारगिल युद्ध के कारण पूरे देश में बही राष्ट्रवादी बयार ने भाजपा की सत्ता में वापसी करा दी थी। तब महज 114 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था।

राजनीतिक रणनीतिकार इस बात से सहमत नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई ने एक बार फिर से पूरे आमचुनाव को राष्ट्रवाद पर केंद्रित कर दिया है। राष्ट्रवाद के साये में होने वाले आम चुनाव में पार्टी के पास सबसे बड़ा राष्ट्रवादी सियासी चेहरा पीएम मोदी है। विपक्षी एका और बड़े राज्यों में विपक्षी गठबंधन से चिंता में पड़ी पार्टी इस चुनाव को किसी भी तरह से स्थानीय मुद्दों के इतर नेतृत्व के मुद्दे पर केंद्रित करना चाहती थी।

अब वायु सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही न सिर्फ सारे स्थानीय मुद्दों के हवा हो जाने की संभावना बन गई है, बल्कि पार्टी को यह भी लगता है कि निर्णायक पीएम के सवाल पर अपने अपने राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों को भी बीते चुनाव की तरह इस बार भी नुकसान उठाना होगा। गौरतलब है कि तब कई राज्यों में लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी से नाराजगी न होने केबावजूद महज मोदी के नाम पर भाजपा के पक्ष में वोट दिया।

1999 में वाजपेयी ने भी बचा ली थी सरकार

भाजपा की रणनीति

राजस्थान की जनसभा से भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाने की रणनीति को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। अब आम चुनाव तक पार्टी के सभी नेता जनसभाओं में अपने भाषण को मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर केंद्रित रखेंगे। इसके अलावा पार्टी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान पीएम की छवि को भुनाने की भी रणनीति बनी है।

अटल की बच गई थी सरकार

बीते सदी के अंत साल 1999 में हुए आम चुनाव में वर्ष 1998 में हुए कारगिल युद्ध के कारण बही राष्ट्रवादी बयार में भाजपा ने अपनी सत्ता बचा ली थी। इससे पहले एक वोट से सरकार गिरने के बाद अगले चुनाव के परिणामों के प्रति भाजपा आशंकित थी। मगर इस चुनाव में पार्टी ने न सिर्फ अपना 182 सीटों का रिकार्ड कायम रखा, बल्कि कांग्रेस के सीटों की संख्या 141 से घट कर 114 रह गई। यह कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार थी । हालांकि वर्ष 2014 के चुनाव में महज 44 सीटें हासिल कर कांग्रेस ने करारी हार का अपना ही कीर्तिमान ध्वस्त कर लिया ।

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स

उत्कृष्ट गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर–द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रुपये, छः माह के लिए 250/रुपये में और घर बैठे पाएं द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

HPKVN | Skill India कौशल भारत-कुशल भारत | N·S·D·C National Skill Development Corporation Transforming the skill landscape | PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास से आएगा निखार खुलेंगे रोज़गार के द्वार

भारत सरकार का उपक्रम

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास प्रशिक्षण का सुनहरा मौका

आईआईआरडी और एचपीकेवीएन के संयुक्त तत्वाधान में

फार्मेसी एसिस्टेंट पाठ्यक्रम में पंजीकरण करवाएं, और अपने कैरियर को दे नई उड़ान

कार्य विवरण	पाठ्यक्रम की विशेषताएं
• दवाईयों की आपूर्ति का रख रखाव एवं प्रबधंन • मरीज का व्यक्तिगत प्रोफाईल तैयार करना जिसमें उसके उपचार और दवाईयो का पृष्ठत विवरण हो	• प्रशिक्षण फ्री, व्यावहारिक प्रशिक्षण • अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

जूनियर साफ्टवेयर डेवेल्पर पाठ्यक्रम में पंजीकरण करवाएं, और अपने कैरियर को दे नई उड़ान

कार्य विवरण	पाठ्यक्रम की विशेषताएं
• सूचना तकनिकी उद्योग /आईटी में प्रारम्भिक स्तर पर सॉफटवेयर तैयार करना एवं उसका परीक्षण करना • कार्यालय में स्वच्छ, स्वस्थ एव सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना	• प्रशिक्षण फ्री, व्यावहारिक प्रशिक्षण • अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पूरा करने पर अभ्यर्थी को अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए कम ब्याज दरों पर बिना गारन्टी के मुद्रा लोन दिलवाने की भी व्यवस्था है

कौशल हिमाचल समृद्ध हिमाचल

ज़िंदगी जियें-नशे को नहीं
स्वस्थ एवं नशामुक्त हिमाचल बनाने में दें सहयोग

IIRD Institute for Integrated Rural Development

IIRD Complex, Bypass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla, H.P.-171006
Phone No. : 0177 2640761, Mob. 91311 24634, 85280 89637
Email : info@missionriev.in, Web : www.missionriev.in

कि दुविधा देखती रह जाए